E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित
राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 12 | अंक : 280 | गुवाहाटी | रविवार, 17 मई, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

बायोलॉजी की शिक्षिका भी गिरफ्तार एनटीए के अफसरों पर गहराया शक पेज 2
वैश्विक ईंधन संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत : असम भाजपा पेज 3
सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भाजपा... पेज 5
सीपीएल 2026 : त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने पोलार्ड, पूरन व नारायण को... पेज 7

सुप्रभात

पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हसेंगे, फिर वो आप से लड़ेंगे, और आप जित जाएंगे।

– अज्ञात

न्यूज गैलरी

असम विस में कांग्रेस को मिलेगा नेता प्रतिपक्ष का दर्जा

गुवाहाटी (हि.स.)। असम विधानसभा में कांग्रेस के लिए एक बड़ी राजनीतिक राहत की खबर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर लागू नियम में संशोधन किए जाने के बाद अब कांग्रेस को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलने जा रहा है। संशोधित नियम के अनुसार अब -शेष पृष्ठ दो पर

कॉकरोच वाली टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया : सीजेआई

नई दिल्ली (हि.स.)। कॉकरोच वाले विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपना बयान जारी किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से ने कल एक तुच्छ मामले की सुनवाई के दौरान मेरी मौखिक टिप्पणियों को किस तरह गलत तरीके से पेश किया है। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी, जिन्होंने फर्जी और नकली डिग्रियों की -शेष पृष्ठ दो पर

असम में भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल बैंक शाखा का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन

गुवाहाटी (एजे/हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को दिसपुर में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल शाखा का आज औपचारिक उद्घाटन किया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस शाखा को पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। दिसपुर फायर स्टेशन के सामने, सचिवालय क्षेत्र के समीप जीएस रोड स्थित सरूमटरिया के जीएस प्वाइंट में स्थापित इस शाखा में ग्राहकों को सेल्फ सर्विस कियोस्क, कैश डिपॉजिट एटीएम तथा त्वरित पेपरलेस खाता खोलने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर बोलते हुए शर्मा ने कहा कि यह शाखा शहरी और वंचित दोनों समुदायों में अधिक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक और कदम है। उन्होंने कहा कि बैंक का उद्घाटन, अपनी *अद्वितीय सेवाओं* के साथ, राज्य सरकार द्वारा कुछ समय से किए जा रहे प्रयासों का सही उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शाखा का उद्घाटन भारतीय बैंकिंग के भविष्य को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए असम की तत्परता को भी दर्शाता है। शर्मा ने कहा कि बैंक के ग्राहक बिना किसी अलग आवेदन के यूपीआई इंटरफेस के माध्यम से सीधे ऋण प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे छोटे दुकानदारों और महिला उद्यमियों को अपने फोन पर मिनटों में अपने व्यावसायिक उपक्रमों के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। शर्मा ने जोर देकर कहा कि असम सरकार राज्य को जिम्मेदार और प्रौद्योगिकी-आधारित निवेश का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार व्यवसायों के फलने-फूलने, युवाओं को अवसर मिलने और प्रत्येक निवासी को बेहतर जीवन बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक एआई-सक्षम स्व-सेवा कियोस्क, कागज रहित नकद जमा और निकासी तथा सुव्यवस्थित डिजिटल ऑनबोर्डिंग के माध्यम से भौतिक और डिजिटल सेवाओं का सहज मिश्रण प्रदान करता है। मालूम हो कि शाखा में एआई और यूपीआई आधारित तकनीक का इस्तेमाल कर बैंकिंग सेवाओं को अधिक तेज और सरल बनाया गया है। ग्राहक यहां सीधे पहुंचकर बचत खाता खोल सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए आवेदन कर सकते हैं, यूपीआई लेनदेन कर सकते हैं तथा विभिन्न बैंकिंग उत्पादों की जानकारी डिजिटल कियोस्क के माध्यम से -शेष पृष्ठ दो पर

एनआरसी की *खराब* वेबसाइट और दोषपूर्ण हेल्पलाइनों पर असम कांग्रेस ने जताई चिंता

गुवाहाटी। पूर्व विपक्ष नेता और कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया ने असम की आधिकारिक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) वेबसाइट और उससे जुड़े सार्वजनिक हेल्पलाइन नंबरों की दयनीय और बेहद गैर-पेशेवर स्थिति की ओर ध्यान दिलाया है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि मैं आपका ध्यान असम की आधिकारिक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) वेबसाइट और उससे जुड़े सार्वजनिक हेल्पलाइन नंबरों की दयनीय और बेहद गैर-पेशेवर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में, अपने एनआरसी विवरण प्राप्त करने का प्रयास करते समय, मुझे एक पूरी तरह से ध्वस्त प्रशासनिक तंत्र का सामना करना पड़ा। मुझे अपना आवेदन रसीद नंबर (एआरएन) प्राप्त करना था और मैंने पोर्टल पर *अपना एआरएन जानें* अनुभाग पर गया। वेबसाइट ने मुझे निर्दिष्ट राज्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के लिए कहा। -शेष पृष्ठ दो पर

सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है सीमा वार्ता : अतुल बोरा

गुवाहाटी। सीमा सुरक्षा एवं विकास विभाग के प्रभार के साथ-साथ कई अन्य विभागों का पुनर्आवंटन होने के कुछ दिनों बाद, मंत्री अतुल बोरा ने शनिवार को जनता भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। विभागीय गतिविधियों की नवीनतम स्थिति की समीक्षा करने के बाद, बोरा ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए और इस बात पर जोर दिया कि सरकार *वार्ता और आपसी समझ* के माध्यम से सीमा विवादों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए बोरा ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत पहले से ही चल रही है और उन्हें उत्साहजनक सहयोग प्राप्त हुआ है। बोरा ने कहा कि संवाद और चर्चा के -शेष पृष्ठ दो पर

राज्य में यूसीसी का कदम *हिंदू-मुस्लिम विभाजन* के उद्देश्य से लिया गया : एआईयूडीएफ

गुवाहाटी। असम सरकार के समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के फैसले की एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम ने आज आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह कदम हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, एआईयूडीएफ नेता ने कहा कि सरकार को इसके बजाय ईंधन की बढ़ती कीमतों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। असम में नई सरकार बनने के बाद, उन्होंने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में यूसीसी (यूसीसी) लागू करने का फैसला कर लिया। सरकार को पेट्रोल, -शेष पृष्ठ दो पर

असम में बारिश का कहर कछार में निर्माणाधीन पुल टूटा

गुवाहाटी (हि.स.)। असम में बीते 72 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश और तूफान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। खासकर बराक घाटी में बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है। लगातार वर्षा के चलते कई इलाकों में जलस्तर बढ़ गया है तथा सड़क एवं पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कछार जिले की बरखला नदी पर निर्माणाधीन एक पुल का हिस्सा अचानक टूटकर नदी में समा गया। यह पुल पुरंदरपुर और बदरपुर को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। बताया गया है कि लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था। लगातार बारिश और तेज -शेष पृष्ठ दो पर

ऊर्जा संकट से दुनिया की उपलब्धियां खतरे में भारत बनेगा वैश्विक विकास इंजन : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हेग में वैश्विक ऊर्जा संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि दुनिया ने समय रहते इस चुनौती का समाधान नहीं किया, तो पिछले कई दशकों में हासिल की गई विकास संबंधी उपलब्धियां नष्ट हो सकती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया की बड़ी आबादी एक बार फिर गरीबी के जाल में फंस सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की छह दिवसीय विदेश यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड पहुंचे हैं। यहां भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया लचीली और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) की आवश्यकता महसूस कर रही है। भारत और नीदरलैंड मिलकर पारदर्शी एवं विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू होने के बाद नीदरलैंड यूरोप का प्रमुख प्रवेश द्वार बन सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि मुख्य भूमि यूरोप में भारतीय मूल के लोगों का सबसे बड़ा समुदाय नीदरलैंड में निवास करता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक प्रतीकों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार भारत कमल के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नीदरलैंड ट्यूलिप के लिए प्रसिद्ध है। -शेष पृष्ठ दो पर

तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

कोलकाता (हि.स.)। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने और उकसावे वाली भाषा इस्तेमाल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। शुक्रवार शाम को विधाननगर साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने राजीव सरकार नामक एक व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता राजीव सरकार ने गत पांच मई को बागुईआटी थाने में शिकायत दी थी। उसी शिकायत के आधार पर अभिषेक के खिलाफ कुल छह धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती थी। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192, 196, 351(2) और 353(1)(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उन पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125 भी लगाई -शेष पृष्ठ दो पर

आंध्र प्रदेश : ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा पैसा

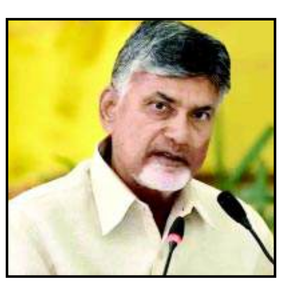

अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आज राज्य में घटती जनसंख्या दर को रोकने के लिए बड़ा ऐलान किया। श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेटा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नायडू ने कहा कि तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवार को 30 हजार रुपए और चौथे बच्चे पर 40 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार अगले एक महीने में इस योजना का विस्तृत खाका जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा स्वर्ण आंध्र-स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। नायडू ने कहा, मैंने नया फैसला -शेष पृष्ठ दो पर

विस चुनाव में वोटिंग के मामले में बंगाल ने त्रिपुरा को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार स्वतंत्रता के बाद का सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया। इस राज्य ने वोटिंग के मामले में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए त्रिपुरा को पीछे छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में विगत 23 एवं 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान हुआ था। चुनाव आयोग (ईसीआई) के जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बंगाल में कुल 93.71 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जिससे साल 2013 का त्रिपुरा का रिकॉर्ड टूटा है। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों में त्रिपुरा ने 93.61 प्रतिशत वोटिंग के साथ देश में सबसे अधिक मतदान दर्ज करने का गौरव हासिल किया था, जो अब बंगाल के नाम हो गया है। इससे पहले बंगाल में अब तक का सबसे अधिक मतदान साल 2013 में 84.72 प्रतिशत दर्ज किया गया था। इस बार बंगाल ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को बहुत बड़े अंतर से तोड़ा है। पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर में पिछले कई वर्षों से विधानसभा चुनावों में 90 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान होता आ रहा -शेष पृष्ठ दो पर

थाईलैंड में मालगाड़ी-बस की टक्कर में आठ लोगों की मौत, 32 घायल

बैंकॉक (हि.स.)। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शनिवार को एक दर्दनाक रेल हादसे में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक मालगाड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी एक सार्वजनिक बस से टकरा गई। टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई, जिसने आसपास मौजूद कुछ अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों के अनुसार हादसा एयरपोर्ट रेल लिंक के मक्कासन स्टेशन के पास हुआ। दुर्घटना के बाद मौके पर तुरंत दमकल और राहत-बचाव दल पहुंचा और आग बुझाने के साथ घायलों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया -शेष पृष्ठ दो पर

भारत में सूखा-भीषण गर्मी पड़ने की आशंका

सुपर अल नीनो मई-जुलाई से सर्दियों तक जारी रहने के आसार

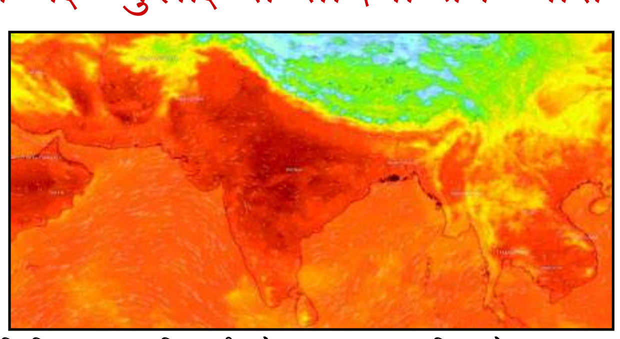

नई दिल्ली। भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश के अनुमान के बीच सुपर अल-नीनो भी एक्टिव हो सकता है। अमेरिकी मौसम एजेंसी नेशनल ओशेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (नोआ) के अनुसार यह मई-जुलाई के दौरान ही दस्तक दे सकता है। नोआ ने बताया कि प्रशांत महासागर का तापमान इस बार मई में सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यह गर्मी की स्थिति इस बार पूरे मानसून सीजन के दौरान बनी रह सकती है। पिछले महीने जारी अनुमान में यह संभावना 61 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 82 प्रतिशत हो गई है। भारतीय मौसम विभाग के चीफ मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि इसका सीधा असर मानसून की बारिश पर पड़ेगा। इससे देश में सूखे का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अल नीनो के कारण समुद्र का पानी असमान्य रूप से गर्म हो जाता है, जिसके साथ हवा के पैटर्न में भी बदलाव आता है। इसके असर से दुनियाभर में बारिश का चक्र बिगड़ जाता है। कहीं भयंकर सूखा तो कहीं मूसलाधार बारिश और बाढ़ आती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब अल-नीनो एक्टिव होगा, तब प्रशांत महासागर से भारत की तरफ आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक देगा। -शेष पृष्ठ दो पर

बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाक

सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सख्त न्यायाधिकरण के निर्णय को किया खारिज

नई दिल्ली। भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े तथाकथित न्यायाधिकरण यानी *कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन* (सीओए) को एक बार फिर अवैध करार देते हुए उसके फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर शनिवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया। इसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा कि भारत ने इस तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय को कभी कानूनी मान्यता नहीं दी और उसके किसी भी निर्णय, कार्यवाही या आदेश का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दरअसल, पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में भारत की किशनगंगा और रतले पनबिजली -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा

बायोलॉजी की शिक्षिका भी गिरफ्तार एनटीए के अफसरों पर गहराया शक

नई दिल्ली। केमेस्ट्री का पेपर लीक करने वाले लेक्चरर पीवी कुलकर्णी के बाद सीबीआई ने बायोलाजी का पेपर लीक करने वाली मनीषा गुरूनाथ मंडहरे को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पूणे के रहने वाले हैं। पीवी कुलकर्णी की तरह बोटनी (वनस्पति विज्ञान) की वरिष्ठ शिक्षिका मनीषा गुरूनाथ ने भी मनीषा बाघमरे के घर पर स्पेशल क्लास में छात्रों को बोटनी और जूलाजी दोनों के प्रश्नपत्र व उत्तर बताए थे, जो बाद में नीट की परीक्षा में हू-ब-हू आए। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की जांच नीट परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों पर टिक गई है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कुलकर्णी और मंडहरे की गिरफ्तारी के बाद नीट का पेपर पूणे, नासिक, गुरूग्राम होते हुए जयपुर तक पहुंचने और बाद में व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने की सारी कड़ियां खुल गई है और उनमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सिर्फ इस बात का पता लगाया जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा गुरूनाथ मंडहरे को ये पेपर किसने दिए। सीबीएससी, जेईई, नीट समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी विषयों के प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए पूरे देश से शिक्षकों के पैनल बनाने का प्रोटोकाल है। हर विषय के 100-150 शिक्षकों द्वारा अलग-अलग तैयार प्रश्नों को मिलाकर अंतिम प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। यानी किसी भी शिक्षक को यह नहीं पता होता है कि उसका कौन सा प्रश्न अंतिम प्रश्नपत्र में शामिल होगा। लेकिन कुलकर्णी और मंडहरे के पास केमेस्ट्री और बायोलाजी के सारे प्रश्न थे, जिन्हें उन दोनों ने मनीषा बाघमरे के घर पर छात्रों को बताया। जांच से जुड़े सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अंतिम प्रश्नपत्र की जानकारी एनटीए में चंद शीर्ष अधिकारियों को होती है। इन्हीं अधिकारियों की प्रश्नपत्र के प्रिंटिंग प्रेस से छपने की प्रक्रिया की निगरानी करने की जिम्मेदारी होती है। पीवी कुलकर्णी और मनीषा गुरूनाथ मंडहरे के प्रश्न पत्र तैयार करने वाली टीम में शामिल होने से इस आशंका की पुष्टि होती है कि इन दोनों को जानने वाले एनटीए के किसी वरिष्ठ अधिकारी, जिसकी पहुंच अंतिम प्रश्नपत्र तक थी, ने पेपर लीक कर दिया। बोटनी की शिक्षिका होने के बावजूद जिस तरह से मंडहरे ने जूलाजी के प्रश्न भी छात्रों को बताए, उससे इस आशंका को और बल मिलता है। सीबीआई यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि प्रश्न पत्र सिर्फ कुलकर्णी को लीक किए गए थे या फिर दोनों को।

जमात-ए-इस्लामी ने भोजशाला मामले में एचसी के फैसले पर जताई चिंता

नई दिल्ली (हि.स.)। जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर गहरी चिंता जताई है जिसमें कमाल मौला मस्जिद को मंदिर बताया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सौहार्द और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने पर गंभीर परिणाम होंगे। जमात-ए-इस्लामी के अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 के तहत दिए गए धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल खड़े करता है। दशकों तक भोजशाला परिसर एक ऐसे प्रबंधन के तहत संचालित होता रहा जिसने दोनों समुदायों को अपनी-अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने की अनुमति थी। एक समुदाय के स्थापित इबादत के अधिकारों को हटाकर दूसरे समुदाय को प्राथमिकता देना न केवल एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान के सिद्धांत को भी कमजोर करने का जोखिम पैदा करता है। इस तरह के घटनाक्रमों को अत्यंत सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए और भारत जैसे बहुलवादी एवं विविध समाज में अपेक्षित नाजुक संतुलन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हुसैनी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को उनके स्थापित इबादतगाह के बदले कोई वैकल्पिक जमीन आवंटित करने का सुझाव भी चिंताजनक है। धार्मिक अधिकारों को महज भौतिक स्थान या विस्थापन के सवालों तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इबादतगाह ऐतिहासिक निरंतरता, पहचान और सामूहिक स्मृति से गहरे तौर पर जुड़े होते हैं।

दिल्ली-त्रिपुरा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से तीन करोड़ का अवैध सोना बरामद

गुवाहाटी (हिंस)। असम के बंगाईगांव जिले में अंतर्राज्यीय तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने दिल्ली-त्रिपुरा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से करीब तीन करोड़ मूल्य के अवैध सोने की खेप बरामद की है। जीआरपी ने शनिवार को बताया कि रेलवे मार्ग से तस्करी कर भारी मात्रा में सोना ले जाए जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद जीआरपी ने ट्रेन में विशेष तलाशी अभियान चलाया। बंगाईगांव जिले से गुजरने के दौरान पुलिसकर्मियों ने ट्रेन के भीतर सघन जांच शुरू की। जांच के दौरान एक यात्री की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। इसके बाद उसके सामान की तलाशी लेने पर बैग के भीतर छिपाकर रखी गई सोने की छड़ें बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रबीन सिंघा राव के रूप में हुई है। फिलहाल, उसे हिरासत में लेकर बंगाईगांव जीआरपी थाने में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस मामले का संबंध किसी बड़े अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह से हो सकता है। बरामद सोने की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इसकी जांच जारी है।

कामरूप महानगर जिले में विश्व डेंगू दिवस का आयोजन

गुवाहाटी (हिंस)। कामरूप महानगर जिले में शनिवार को विश्व डेंगू दिवस विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में डेंगू रोकथाम और नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम महानगर के सोनाराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सेवानिवृत्त सहायक स्वास्थ्य सेवा संचालक डॉ. कुमारेंद्र नाथ, महानगर के जनरल मलेरिया अधिकारी डॉ. विकास रंजन गोगोई, विद्यालय के अकादमिक इंचार्ज हिमांशु नाथ, जिला मलेरिया अधिकारी मृदुल तालुकदार, वाहक जनित रोग नियंत्रण योजना की जिला परामर्शदाता डॉ. सुदर्शना महंत तथा जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट तृषा कटकी सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्रों के बीच डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता सभा, क्विज प्रतियोगिता तथा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने डेंगू से बचाव के लिए साफ-सफाई बनाए रखने, घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने तथा मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने पर विशेष जोर दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि डेंगू एक गंभीर लेकिन रोकथाम योग्य बीमारी है। समय रहते सावधानी बरतने और जनसहभागिता बढ़ाने से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है।

सड़क दुर्घटना में डकैती का आरोपी घायल

नगांव (हिंस)। नगांव जिले के मोरीकलंग इलाके में हाल में हुई डकैती के एक मामले में शामिल मुख्य आरोपी बीती रात सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि बीती रात पुलिस मोरीकलंग इलाके में हुई डकैती मामले में शामिल मुख्य आरोपी रजीबुल इस्लाम को एक वाहन से ले जा रही थी। डकैती के दौरान लूटी गई सोने की चेन तलाश करने जा रही पुलिस की वाहन अन्य एक वाहन से जा टकराई। जिसमें रजीबूल इस्लाम गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए गंभीर अवस्था में नगांव चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती कराया गया है।

पूसीरे के सभी मंडलों का अप्रैल, 2026 में माल परिवहन के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन

गुवाहाटी (हिंस)। माल परिवहन कारोबार के क्षेत्र में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) अपने सभी मंडलों में लोडिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ-साथ इस क्षेत्र में व्यापार तथा सामग्रियों की आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई नीतिगत पहलों के कारण निरंतर मजबूत गति बनाए हुए है। एक प्रमुख परिचालन विकास के तहत, कटिहार मंडल के अधीन रहमतपुर और पौआखाली स्टेशनों को 16 अप्रैल से, जावक और आवक दोनों तरह के माल परिवहन के संचालन के लिए खोल दिया गया है। इसमें घरेलू और बांग्लादेश जाने वाला परिवहन भी शामिल है। बांस परिवहन को प्रोत्साहित करने और इससे जुड़े उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिए कवर्ड वैगनों में बिजी सीजन सरचार्ज के छूट को एक मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पूसीरे से शुरू होने वाले बांस के सभी परिवहनों पर यह सुविधा लागू की गई है। पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने शनिवार को बताया कि इस अवधि के दौरान, अलीपुरद्वार मंडल ने धुपगुड़ी स्टेशन से न्यू तिनसुकिया और शालचापरा स्टेशनों तक आलू के 378 वैगनों वाले 09 रेकों की लोडिंग दर्ज की, जिससे 1.61 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। कटिहार मंडल के अंतर्गत, पूर्णिया जंक्शन और जलालगढ़ स्टेशनों से मक्का के 126 वैगनों वाली 03 रेक लोड किए गए, जिससे 0.33 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। लामडिंग मंडल ने कई प्रकार की सामग्रियों के लोडिंग क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया।

पृष्ठ एक का शेष

असम में भारत की पहली ...

प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ रणनीतिक विलय के बाद स्लाइस ने एकीकृत फुल-स्टैक बैंकिंग इकोसिस्टम तैयार किया है, जिसके तहत पारंपरिक बैंकिंग और फिनटेक सेवाओं को एक मंच पर लाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह पहल असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिजिटल वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के साथ तकनीक आधारित बैंकिंग सेवाओं को नई दिशा देगी।

एनआरसी की खराब वेबसाइट...

इस नंबर पर कॉल करने पर लगातार घंटी बजती रही, लेकिन कोई जवाब या स्वीकृति नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय नेटवर्क में तकनीकी खराबी मानकर, मैंने बाद में असम के बाहर पंजीकृत सिम कार्ड का उपयोग करके असम के बाहर की पूछताछ के लिए निर्धारित टोल-फ्री नंबर 18003453762 पर कॉल किया। हैरानी की बात है कि इस सरकारी हेल्पलाइन ने मुझे शिलांग के एक पशु चिकित्सालय से जोड़ दिया। बुनियादी ढांचे की इस स्तर की लापरवाही बिल्कुल अस्वीकार्य है। असम में एनआरसी प्रक्रिया एक विशाल और अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया थी जिस पर जनता का भारी भरकम खर्च 1,600 करोड़ रुपए से अधिक था। इस भारी खर्च के बावजूद, राज्य बुनियादी डिजिटल ढांचे को सुव्यवस्थित करने या चालू टेलीफोन लाइनों को बनाए रखने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि असम के नागरिकों को अनेक कानूनी और प्रशासनिक कारणों से एनआरसी दस्तावेज और उससे संबंधित डेटा की अक्सर आवश्यकता होती है। फिर भी, पोर्टल की वर्तमान स्थिति के कारण व्यक्ति अपने डेटा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एनआरसी डेटा के आईटी रखरखाव के लिए आवंटित भारी धनराशि का हिसाब-किताब किसका है? इस पोर्टल और हेल्पलाइन की उपेक्षित स्थिति को देखते हुए, क्या राज्य सरकार ने एनआरसी के महत्व और वैधता को पूरी तरह से नकार दिया है? यदि एनआरसी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना हुआ है, तो यह सरकार का मूलभूत कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि नागरिक इस तरह की घोर प्रशासनिक उपेक्षा का सामना किए बिना अपने विवरण प्राप्त कर सकें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस मामले की तत्काल जांच करें, एनआरसी वेबसाइट की कार्यक्षमता बहाल करें, डायवर्ट किए गए हेल्पलाइन नंबरों को ठीक करें और यह सुनिश्चित करें कि एक समर्पित सहायता टीम नागरिकों के प्रश्नों का सक्रिय रूप से प्रबंधन कर रही हो। असम के लोगों को इस घोर लापरवाही के लिए एक पारदर्शी स्पष्टीकरण मिलना चाहिए।

सकारात्मक रूप से ...

माध्यम से सीमा विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया जारी है। हमें सभी पड़ोसी राज्यों से सहयोग मिला है और मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा एवं विकास विभाग के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों और कल्याण को प्राथमिकता देना जारी रखेगी, साथ ही लंबे समय से लंबित विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में भी प्रयास करेगी। बोरा की ये टिप्पणियां असम-मेघालय सीमा पर, विशेष रूप से लापंगाप क्षेत्र में, नए सिरे से बढ़े तनाव के बीच आई हैं, जहां इस सप्ताह की शुरुआत में स्थानीय निवासियों के विरोध प्रदर्शनों के कारण स्पेशल फोर्स-10 कमांडो सहित कई पुलिस प्लाटून तैनात किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था में यह सुदृढ़ीकरण ग्रामीणों के बीच बढ़ते असंतोष के बाद किया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि असम के कार्बी आंगलोंग जिले के व्यक्तियों द्वारा बार-बार उत्पीड़न के कारण उन्हें कृषि गतिविधियों को करने से रोका जा रहा है। लापांगप के पास के गांवों को लेकर विवाद दशकों से जारी है , जिसमें असम और मेघालय दोनों ही इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। मेघालय इस क्षेत्र को ब्लॉक 1 कहता है और ऐतिहासिक स्वामित्व का दावा करता है, जबकि वर्तमान में इस क्षेत्र का प्रशासन असम की कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) द्वारा किया जाता है। अन्य पांच विवादित स्थानों के साथ-साथ इस क्षेत्र पर भी पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों के बीच सीमा वार्ता के दूसरे चरण के दौरान चर्चा होने की उम्मीद है। बोरा ने यह भी कहा कि असम समझौते का कार्यान्वयन भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहेगा। उन्होंने कहा कि असम समझौते के कार्यान्वयन विभाग की प्रगति को महत्व दिया जाएगा। सरकार कार्यान्वयन प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री जी ने आगे बताया कि उनके कार्यभार संभालने के तुरंत बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए एक विस्तृत 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार की गई थी। आज हमने प्रधान सचिव और विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण विभाग है। महात्मा गांधी की परिकल्पना के अनुसार, राज्य की समग्र प्रगति के लिए गांवों का विकास आवश्यक है, बोरा ने कहा। सरकार के ग्रामीण विकास एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए बोरा ने कहा कि प्रत्येक परिवार, विशेष रूप से चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए आवास सुविधाओं को सुनिश्चित करना एक प्रमुख प्राथमिकता बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को घर मिले, विशेषकर चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को। हमने स्वयं सहायता समूहों के विकास को प्राथमिकता देने का भी निर्णय लिया है। विकास गतिविधियों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी, इस बात पर जोर देते हुए बोरा ने कहा कि वीबी-ग्रामजी जैसी पहल, एमजीएनआरईजीए के साथ मिलकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के नए अवसर पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। पहले एमजीएनआरईजीए था, अब वीबी-ग्रामजी पहल भी ग्रामीण विकास के लिए नए अवसर पैदा कर रही हैं। मंत्री ने उत्पाद शुल्क विभाग के प्रदर्शन पर भी प्रकाश डाला और कहा कि इसने पिछले वित्तीय वर्ष में पर्याप्त राजस्व अर्जित किया और दक्षता और राजस्व संग्रह में सुधार के लिए नई रणनीतियों को अपनाना जारी रखेगा। समावेशी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बोरा ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और कल्याण प्राथमिकता बनी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना हमारी सरकार की पहली जिम्मेदारियों में से एक है, और उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता बना रहेगा।

असम में बारिश का ...

बहाव के कारण पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। वहीं, पड़ोसी हैलाकांदी जिले में भी प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण पांचग्राम और मुकाम कुटी को जोड़ने वाला आरसीसी पुल भरभराकर टूट गया। पुल ध्वस्त होने के बाद दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क पूरी तरह से कट गया है। सूत्रों के अनुसार कई दिनों से जारी धारा प्रवाह बारिश के कारण नदियों और जलधाराओं का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। अत्यधिक दबाव के चलते पुल अचानक टूट गया। इस मार्ग पर निर्भर कई गांवों के हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। ग्रामीणों को अब आवागमन के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक जरूरतों की आपूर्ति और आपातकालीन सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए रखी है। प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक संपर्क व्यवस्था बहाल करने तथा नुकसान का आकलन करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

ऊर्जा संकट से दुनिया...

ट्यूलिप और कमल दोनों यह सिखाते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हों या मिट्टी में, सौंदर्य और शक्ति दोनों प्राप्त की जा सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत में लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। जब आम नागरिकों को अपने सपनों की पूर्ति और विकास में भागीदारी दिखाई देती है, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार लगभग 90 प्रतिशत तक मतदान दर्ज किया गया, जो लोकतंत्र के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 16 मई की तारीख का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में इसी दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे और दशकों बाद देश में स्थिर एवं पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि 13 वर्ष मुख्यमंत्री और 12 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में देश सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। करोड़ों देशवासियों का लगातार समर्थन उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह बहुत छोटी उम्र में ही देशभक्ति के रंग में रंग गए थे। उन्होंने *अहम् से वयम्* का मार्ग चुना और अब जनता का सुख ही उनका सुख तथा जनता का कल्याण ही उनका कर्तव्य बन गया है। उन्होंने कहा कि आज भारत केवल बदलाव नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनने का सपना देख रहा है। देश सबसे तेज विकास, आधुनिक तकनीक और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत केवल अपनी सीमाओं तक सीमित सोच वाला देश नहीं है, बल्कि वह दुनिया का विकास इंजन बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत ओलंपिक की मेजबानी, वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने और ग्रीन एनर्जी में नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में 12 सेमीकंडक्टर संयंत्रों पर काम चल रहा है, जिनमें से दो में उत्पादन शुरू हो चुका है। अब चिप भी *डिजाइन इन इंडिया* और *मेड इन इंडिया* होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीदरलैंड आकर उन्हें भारत जैसा अनुभव हो रहा है। यहां की प्रगति में भारतीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है और इस पर हर भारतवासी को गर्व है। उन्होंने कहा कि यहां बसे भारतीय परिवारों की कहानियां केवल प्रवास की नहीं, बल्कि संघर्ष और सफलता की कहानियां हैं। समय बदला, देश बदले और पीढ़ियां बदलीं, लेकिन भारतीय संस्कार, परिवार व्यवस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव आज भी जीवित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों ने डच भाषा को अपनाया, लेकिन अपनी मातृभाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को भी संजोकर रखा। भारतीय संगीत और संस्कृति आज नीदरलैंड के परिवारों तक पहुंच रही है।

राज्य में यूसीसी का ...

डीजल और खाना पकाने की गैस की बढ़ती कीमतों को रोकने पर ध्यान देना चाहिए था और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, इस्लाम ने कहा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रस्तावित यूसीसी का उद्देश्य मुसलमानों के रीति-रिवाजों और परंपराओं को निशाना बनाना है। उन्होंने कहा कि उनके यूसीसी का सीधा उद्देश्य मुसलमानों के रीति-रिवाजों और परंपराओं पर हमला करना है। हम यूसीसी के इस कार्यान्वयन का कड़ा विरोध करेंगे। असम सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित कानून में न्यूनतम विवाह आयु, बहुविवाह निषेध, महिलाओं के संपत्ति अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के नियमन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि आदिवासी समुदायों को छूट दी जाएगी और पारंपरिक रीति-रिवाजों और मान्यताओं की रक्षा की जाएगी।

तृणमूल सांसद अभिषेक ...

गई है। पुलिस की एफआईआर में कहा गया है कि आरोपित ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया था। शिकायतकर्ता राजीव सरकार ने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटती, तो आम लोगों पर हमले हो सकते थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी शिकायत किसी भी तरह से राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है। राजीव सरकार खुद को समाजसेवी बताते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

आंध्र प्रदेश : ज्यादा बच्चे ...

लिया है। तीसरे बच्चे के जन्म पर 30 हजार रुपए और चौथे बच्चे पर 40 हजार रुपए दिए जाएंगे। क्या यह सही फैसला नहीं है? दिलचस्प बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू पहले जनसंख्या नियंत्रण के समर्थक माने जाते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि समय बदल चुका है और समाज को जन्म दर बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना होगा। इससे पहले सरकार दूसरे बच्चे के जन्म पर 25 हजार रुपए देने की योजना पर भी विचार कर रही थी। 5 मार्च को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बताया था कि राज्य सरकार दूसरे बच्चे के जन्म पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने पर विचार कर रही है। हालांकि बाद में स्वास्थ्य मंत्री सत्या कुमार यादव ने कहा कि सरकार अब तीसरे और उससे अधिक बच्चों वाले परिवारों को भी प्रोत्साहन देने का फैसला कर चुकी है। नायडू ने कहा कि आय बढ़ने के साथ कई दंपति केवल एक बच्चा पैदा करने का फैसला कर रहे हैं। वहीं कुछ परिवार तब तक दूसरा बच्चा नहीं चाहते जब तक पहला बेटा न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि इन कारणों से राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर लगातार घट रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज की आबादी स्थिर बनाए रखने के लिए कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.1 होना जरूरी है। यानी औसतन हर महिला के दो से अधिक बच्चे होने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कई देशों में घटती आबादी और बुजुर्ग होती जनसंख्या ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है।

विस चुनाव में वोटिंग...

है लेकिन इस बार बंगाल के आगे सब पीछे छूट गए। अप्रैल में हुए मतदान के बाद एक मई को बंगाल का अनंतिम मतदान 92.67 प्रतिशत था, जिसने तभी नागालैंड और मणिपुर को पीछे छोड़ दिया था। गुरुवार को जारी अंतिम आंकड़ों में यह ग्राफ बढ़कर 93.71 प्रतिशत पर पहुंच गया, जिसने त्रिपुरा के सर्वकालिक रिकॉर्ड को भी मात दे दी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के चुनाव में मतदान केंद्रों पर 92.69 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 90.92 रहा। तमिलनाडु में महिलाओं की भागीदारी 85.76 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 83.57 रहा। अन्य राज्यों में असम और पुडुचेरी भी टूटे रिकॉर्ड। नौ अप्रैल को हुए मतदान में असम में 85.38 प्रतिशत और पुडुचेरी में 89.83 प्रतिशत मतदान हुआ। तमिलनाडु में कुल 84.69 प्रतिशत वोटिंग हुई जिसने 2011 के 78.29 प्रतिशत के अपने पिछले रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक साथ 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में संपन्न कराया गया। त्रिपुरा में साल 2013 में 93.61 प्रतिशत, साल 2008 में 92.49 प्रतिशत और साल 2018 में 91.38 प्रतिशत भारी मतदान दर्ज किया गया था। नागालैंड में साल 2013 के चुनाव में 91.62 प्रतिशत और साल 1993 में 91.53 प्रतिशत वोट पड़े थे। मणिपुर ने भी सूची में कई बार जगह बनाई है, जहां साल 1995 में 91.41 प्रतिशत, साल 2002 में 90.38 प्रतिशत, साल 1990 में 89.95 प्रतिशत और साल 2000 में 89.87 प्रतिशत मतदान हुआ था। पुडुचेरी में साल 2026 के विधानसभा चुनाव में 89.87 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई है, जो मणिपुर (साल 2000) के बराबर ही है।

थाईलैंड में मालगाड़ी-बस...

है कि बस रेलवे ट्रैक पर लाल सिग्नल के कारण रुकी हुई थी, जिससे रेलवे क्रॉसिंग के सुरक्षा बैरियर पूरी तरह बंद नहीं हो सके। इसी दौरान कंटेनर लेकर जा रही मालगाड़ी समय रहते नहीं रुक सकी और बस से जा टकराई। उप परिवहन मंत्री सिरिपोंग अंगकासाकुलकियात ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी आठ लोग बस में सवार थे। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के तुरंत बाद आग लग गई और कई वाहन ट्रैक के आसपास फंस गए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में ट्रेन को बस और अन्य वाहनों को पटरी के साथ घसीटते हुए देखा गया। राहत कर्मियों ने आग पर काबू पाने के बाद क्षेत्र को सुरक्षित करने, गैस रिसाव रोकने और मलबे में फंसे लोगों की तलाश का काम जारी रखा। फिलहाल अधिकारी दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर रहे हैं।

भारत में सूखा-भीषण ...

इससे बारिश पर असर पड़ेगा। नोआ के नए अपडेट के मुताबिक इस साल मई से जुलाई के दौरान सुपर अल नीनो डेवलप होने की 82 प्रतिशत संभावना है। इसके सर्दियों (दिसंबर 2026 से फरवरी 2027) तक जारी रहने की 96 प्रतिशत आशंका है। जबकि, इसके *स्ट्रॉन्ग* या *वेरी स्ट्रॉन्ग* रहने की करीब 67 प्रतिशत आशंका है। इससे, कमजोर मानसून, सूखे और हीटवेव की आशंका अब ज्यादा हो गई है। उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति बनने का सबसे ज्यादा खतरा है, जिससे लंबे सूखे और कृषि नुकसान की आशंका बढ़ सकती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान अगस्त-सितंबर के दौरान सबसे संवेदनशील राज्यों में माने जा रहे हैं। वहीं मध्य और पश्चिम भारत में जहां अच्छी बारिश होती है वहां भी सामान्य से कम बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर और नर्मदापुरम संभागों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। हालांकि लद्दाख, राजस्थान के कुछ हिस्से, तेलंगाना, साथ ही उत्तर भारत के कुछ हिस्से में इसका असर कम होगा। दुनिया में कुल मिलाकर बारिश बढ़ रही है, इसके बावजूद जमीन और इकोसिस्टम ज्यादा सूखे हो रहे हैं। नेचर में प्रकाशित एक नई स्टडी के मुताबिक, अब बारिश सालभर में बराबर बंटने के बजाय बड़े और ज्यादा तेज तूफानी दौर में हो रही है। इनके बीच लंबे ड्राई स्पेल आ रहे हैं। नतीजा यह कि एकसाथ बहुत ज्यादा पानी गिरने से मिट्टी उसे ज्यादा सोख नहीं पाती। पानी सतह पर जमा होता है और जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है।

सिंधु जल संधि पर भारत...

परियोजनाओं को लेकर आपत्ति जताते हुए मामले को हेग स्थित मध्यस्थता तंत्र तक पहुंचाया था। जिसे लेकर भारत का लगातार यह कहना रहा है कि संधि के प्रावधानों के तहत इस तरह के *कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन* का गठन ही अवैध है। भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है। 15 मई 2026 को इस तथाकथित सीओए ने सिंधु जल संधि की व्याख्या और जल भंडारण क्षमता से जुड़े मुद्दों पर एक पूरक फैसला जारी किया, जिसे भारत ने तुरंत खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि भारत की ओर से सिंधु जल संधि को *अबयंस* यानी निलंबित रखने का फैसला अभी भी लागू है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि पर विराम लगा दिया था। भारत ने साफ संकेत दिए थे कि सीमा पार आतंकवाद और जल सहयोग साथ-साथ नहीं चल सकते। अपनी बातों पर रवैया स्पष्ट करते हुए भारत ने संधि के दायित्वों को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला लिया था। भारत का रुख स्पष्ट और सख्त है। ये बताता है कि नई दिल्ली अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मंचों के दुरुपयोग के खिलाफ अधिक आक्रामक और स्पष्ट नीति अपना रही है।

असम विस में कांग्रेस ...

विधानसभा में कम से कम 13 विधायकों वाले दल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्राप्त होगा। पुराने नियम के अनुसार इसके लिए 21 सदस्यों की आवश्यकता थी। वर्तमान में कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं, जिसके चलते पार्टी इस पद की अधिकारिक दावेदार बन गई है। राजनीतिक हलकों में इसे कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। साथ ही अब यह चर्चा भी तेज हो गई है कि कांग्रेस विधायक दल से आखिर किसे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कांग्रेस के 19 विधायकों में 18 मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जबकि एक विधायक हिंदू समुदाय से हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों पर भी नजरें टिक गई हैं।

कॉकरोच वाली टिप्पणी ...

मदद से वकालत जैसे व्यवसायों में प्रवेश किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायों में भी घुसपैठ कर चुके हैं, इसलिए वे परजीवी की तरह हैं। चीफ जस्टिस ने अपने बयान में कहा है कि यह कहना पूरी तरह से बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की मुझे न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं के मन में मेरे लिए बहुत आदर और सम्मान है और मैं भी उन्हें एक विकसित भारत के स्तंभों के रूप में देखता हूं। उल्लेखनीय है कि 15 मई को चीफ जस्टिस ने एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच संबंधी बयान दिया था जिस पर काफी बवाल मचा था।

लोक भवन असम में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस का आयोजन

गुवाहाटी (हिंस)। असम लोक भवन में शुक्रवार को *एक भारत श्रेष्ठ भारत* पहल के तहत सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम लोक भवन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य को शांति, प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सिक्किम देश का पहला पूर्णत: जैविक राज्य बनकर सतत विकास का आदर्श प्रस्तुत कर चुका है और यह साबित किया है कि आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। राज्यपाल ने सिक्किम की इको-टूरिज्म, जैविक कृषि तथा फार्मास्युटिकल क्षेत्र में बढ़ती उपलब्धियों की भी सराहना की। सिक्किम के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वहां के लोगों की सादगी, अपनापन और प्रकृति के प्रति सम्मान उनकी सबसे प्रिय स्मृतियों में शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा, उद्यमिता, स्वयं सहायता समूहों तथा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सिक्किम ने प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास और मजबूत समाज के निर्माण के लिए महिलाओं का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। *एक भारत श्रेष्ठ भारत* की भावना का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में एकता में निहित है। उन्होंने युवाओं से देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और विरासत को समझने एवं अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राज्यपाल के आयुक्त एवं सचिव एसएस मीनाक्षी सुंदरम, सिक्किम की सहायक रेजिडेंट कमिश्नर जशोदा छेत्री, सिक्किम के प्रतिनिधि तथा लोक भवन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

वैश्विक ईंधन संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत : असम भाजपा

गुवाहाटी (हिंस)। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिर एवं दूरदर्शी आर्थिक नीतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी ने दावा किया कि केंद्र सरकार आम जनता को वैश्विक ईंधन संकट के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय बशिष्ठ से जारी आधिकारिक बयान में पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट दिलीप कुमार शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और अस्थिरता का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि दिसंबर, 2025 में कच्चे तेल की कीमत जहां 57 से 62 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के बीच थी, वहीं अब यह बढ़कर 110 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई है, जिससे

दुनिया भर के देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। बयान में कहा गया कि भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 88.3 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। इसके बावजूद मोदी सरकार ने आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देने के लिए निरंतर कदम उठाए हैं। भाजपा नेता ने दावा किया कि कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि की गई है, जबकि भारत में पिछले तीन-चार महीनों के दौरान पेट्रोल की कीमत में लगभग 3.2 प्रतिशत तथा डीजल की कीमत में करीब 3.4 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है, जो विश्व स्तर पर सबसे कम वृद्धि में शामिल है। बयान में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और कूटनीतिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा गया कि पेट्रोलियम भंडारण और एलपीजी आपूर्ति से जुड़े हालिया अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है तथा लोगों में विश्वास पैदा किया है। असम भाजपा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, रणनीतिक दृष्टि और संतुलित आर्थिक नीतियों के बल पर भारत इस वैश्विक संकट का सफलतापूर्वक सामना करेगा। साथ ही राज्य और देश के लोगों से इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार के प्रति सहयोग और समर्थन बनाए रखने की अपील भी की गई।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर असम पुलिस और बीएसएफ ने 14 घुसपैठियों को रोका

गुवाहाटी (हिंस)। असम में नई सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश से लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। असम पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने संयुक्त अभियान चलाकर 14 कथित घुसपैठियों को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि सीमा पर तैनात जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं और घुसपैठ की हर कोशिश को विफल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असम पुलिस और बीएसएफ के सतर्क जवानों ने 14 घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें सीमा पर ही रोक दिया। मुख्यमंत्री ने जवानों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि, इससे एक दिन पहले 14 मई को भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी थी कि असम पुलिस और बीएसएफ ने 12 कथित घुसपैठियों को असम में प्रवेश करने से पहले ही पकड़कर उनकी कोशिश नाकाम कर दी थी।

भारत माला परियोजनाओं से असम में विकास को नई गति

गुवाहाटी (हिंस)। असम में भारतमाला परियोजना और असम माला 3.0 के तहत जारी सड़क एवं राजमार्ग निर्माण कार्य राज्य की कनेक्टिविटी व्यवस्था को तेजी से मजबूत कर रहे हैं। इन परियोजनाओं को पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक गतिविधियों, व्यापारिक संपर्क और सामरिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। असम में राज्य सरकार और केंद्र की संयुक्त पहल के तहत 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 900 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों के निर्माण और विकास का कार्य प्रगति पर है। परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों के साथ-साथ ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों को भी बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के सिलचर-बुद्धनगर खंड को चार लेन में विस्तारित किया जा रहा है। वहीं, डिमा हसाओ जिले में 229 किलोमीटर लंबे आधुनिक और आपदा-प्रतिरोधी राजमार्ग का निर्माण जारी है। यह सड़क भूस्खलन और खराब मौसम की स्थिति में भी यातायात को सुचारु बनाए रखने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त एनएच-306 के सिलचर-वैरेंग्ते-सैरांग मार्ग पर चार लेन सड़क निर्माण का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर असम और मिजोरम के बीच आवागमन और व्यापारिक संपर्क को विशेष मजबूती मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रा समय में कमी आएगी, परिवहन लागत घटेगी और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। पर्यटन, कृषि, चाय उद्योग और छोटे व्यापारिक क्षेत्रों को भी इसका व्यापक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

तेज रफ्तार कार ने उजाड़ा परिवार : चिरांग में सीआईएसएफ जवान और पत्नी की मौत, बेटी जिंदगी की जंग लड़ रही

चिरांग (हिंस)। असम के चिरांग जिले में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों से लौट रहे एक परिवार को मातम में बदल दिया। बिजनी-कोकलुंग सड़क पर उत्तर शिलबाड़ी इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान राहुल राय और उनकी पत्नी अनामिका पाटगिरी राय की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी कस्तूरी राय गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार, परिवार अपने पैतृक गांव में आयोजित वार्षिक पूजा के समापन समारोह में शामिल होकर भूमकीपारा स्थित घर लौट रहा था। इसी दौरान एएस 26 एफ 2229 नंबर की एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उनके स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटर सवार तीनों लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे में अनामिका पाटगिरी राय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राहुल राय को तत्काल बंगाईगांव के लोअर असम अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि राहुल राय इस पूजा में शामिल होने के लिए हाल ही में ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आए थे। दंपति की इकलौती बेटी कस्तूरी राय इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई है और उसका इलाज लोअर असम अस्पताल में चल रहा है।

धुबड़ी : सिविल डिफेंस के तहत आपातकालीन तैयारियों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

धुबड़ी (विभास)। आपातकालीन तैयारी पर एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) धुबड़ी द्वारा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के सहयोग से आपातकालीन सायरन की आवाज से शुरुआत हुई। इसके बाद अग्निशमन सेवाकर्मी सक्रिय हुए और उन्होंने हवाई हमले के कारण लगी आग को बुझाने का प्रदर्शन किया। नागरिक सुरक्षा कर्मियों ने घायलों को बचाया और उन्हें पोर्टेबल स्ट्रक्चर पर एक निश्चित सुरक्षित स्थान में ले गए, जहां प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। प्रदर्शन करने वाली फ्लेक्स बोर्ड लगाया गया था, जिसमें आपातकालीन किट तैयार करना, आपात स्थिति के दौरान शांत रहना, सायरन या ब्लैकआउट के दौरान घबराहट से बचाना, अफवाह फैलाने वालों से बचाना और अनावश्यक यात्रा से बचाने जैसे विषय को शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक करना था।

भारत में सेशेल्स की उच्चायुक्त ने असम के राज्यपाल से मुलाकात की; सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रों पर चर्चा की

गुवाहाटी (विभास)। भारत में सेशेल्स की उच्चायुक्त, हरिसोआ ललातियाना अकोच ने आज लोक भवन में असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और असम तथा सेशेल्स के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। उच्चायुक्त का स्वागत करते हुए, राज्यपाल श्री आचार्य ने कहा कि सेशेल्स अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पारिस्थितिक समृद्धि और अद्वितीय जैव विविधता के लिए विश्व स्तर पर सराहा जाता है। सेशेल्स की दूत का ध्यान आकर्षित करते हुए, श्री आचार्य ने कहा कि भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित असम भी अपनी सुरम्य सुंदरता, जीवंत सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। असम की खूबियों पर प्रकाश डालते हुए, राज्यपाल ने कहा कि यह राज्य विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का घर है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। इसके अलावा, विशाल चाय के बागान, विशाल ब्रह्मपुत्र नदी, अद्वितीय मूगा रेशम, बिहू जैसे रंगीन त्योहार और एक गहरी आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विरासत असम की मुख्य विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य पर्यटन और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए एक गंतव्य के रूप में अपार संभावनाएं प्रदान करता है। राज्यपाल ने असम और सेशेल्स के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों की गुंजाइश के बारे में आशा व्यक्त की, जिससे लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत होंगे और आपसी समझ गहरी होगी। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दूरी के बावजूद, असम

और सेशेल्स जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में समान चिंताओं और हितों को साझा करते हैं। श्री आचार्य ने पारिस्थितिक संरक्षण, सतत पर्यटन प्रथाओं, शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने शैक्षणिक आदान-प्रदान की संभावना और सेशेल्स के छात्रों के लिए असम के शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों का स्वागत किया। राज्यपाल ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम में हो रहे तीव्र परिवर्तन पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, शिक्षा और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में। उन्होंने कहा कि हवाई, रेल, सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग कनेक्टिविटी में सुधार ने अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव और साझेदारी के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। सेशेल्स की उच्चायुक्त ने राज्यपाल को सेशेल्स आने का निमंत्रण दिया, और दोनों ने आने वाले दिनों में असम और सेशेल्स के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती और सार्थक सहयोग की उम्मीद व्यक्त की।

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 का आयोजन

राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, गुवाहाटी में नई सुविधा *ऑर्किड और कैक्टस गार्डन* का उद्घाटन

गुवाहाटी। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, गुवाहाटी-जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई है-18 मई 2026 को विभिन्न गतिविधियों की एक श्रृंखला और *ऑर्किड और कैक्टस गार्डन* के उद्घाटन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 मनाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय है *संग्रहालय: एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते हुए* इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा, रचनात्मकता और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। ऑर्किड और कैक्टस गार्डन का उद्घाटन 18 मई 2026 को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, गुवाहाटी में डॉ. आशिहो ए माओ (पूर्व निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और कुलपति, मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी) द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में श्री ख्यांजित गोगोई (अध्यक्ष, द ऑर्किड सोसाइटी ऑफ ईस्टर्न हिमालय और क्षेत्रीय ऑर्किड जर्मप्लाज्म संरक्षण एवं प्रसार केंद्र) भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से शोभा बढ़ाएंगे। इस पहल को सार्वजनिक जुड़ाव को समृद्ध करने और वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से असम और व्यापक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के युवाओं और छात्रों के बीच। यह पहल आगंतुकों के लिए विशेष रुचि का विषय होगी, क्योंकि इसमें स्वदेशी ऑर्किड प्रजातियों का एक जीवंत प्रदर्शन शामिल है जो उत्तर-पूर्वी भारत की समृद्ध वनस्पति विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं; इसके साथ ही चुनिंदा विदेशी किस्में और उल्लेखनीय सूखा-प्रतिरोधी पौधों की एक प्रदर्शनी भी यहाँ मौजूद होगी, जो जीवित रहने के उनके अद्भुत अनुकूलन को प्रदर्शित करती है। उत्सव के एक भाग के रूप में, 14 से 16 मई 2026 तक सरकारी कला महाविद्यालय, गुवाहाटी के छात्रों द्वारा एक भित्ति चित्रकला सत्र आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की समय-सारिणी में निम्नलिखित कार्यक्रम भी शामिल हैं : 17 मई 2026 को छात्रों और विज्ञान संचारकों के लिए ऑर्किड और कैक्टस के महत्व पर एक कार्यशाला। 18 मई 2026 को कक्षा सिक्स से दसवीं तक के छात्रों के लिए एक *प्रदर्शनी खोज* प्रतियोगिता। गार्डन के उद्घाटन समारोह के बाद, बिहू और ऑर्किड के बीच के शाश्वत संबंध को दर्शाने वाला एक विशेष उद्घाटन सांस्कृतिक कार्यक्रम। 18 मई 2026 को साइंस सेंटर में सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश नि:शुल्क रहेगा, और यह शाम 7:30 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहेगा। नेशनल साइंस सेंटर, गुवाहाटी, छात्रों, शिक्षकों, परिवारों और नागरिकों को इन समारोहों में भाग लेने और विज्ञान, संस्कृति, कला और प्रकृति के अनूठे संगम का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है।

रंगिया : छात्र संघ के संयुक्त तत्वावधान में विशेष सभा आयोजित

रंगिया (विभास)। कामरूप जिला छात्र संस्था के सौजन्य से तथा असम उन्नति सभा कामरूप जिला समिति और रंगिया आंचलिक छात्र संस्था के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को शहीद भवन प्रांगण में एक विशेष सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता असम उन्नति सभा, कामरूप जिला समिति के अध्यक्ष खगेन हीरा ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन सदौं कामरूप जिला छात्र संस्था के महासचिव तौफीकुर रहमान ने किया। सभा में सदौं असम छात्र संस्था के कार्यालय सचिव भवज्येति डेका भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि असम उन्नति सभा हमारी भ्रातृ संगठन है और इसकी कामरूप जिला समिति का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनाना है। भवज्येति ने कहा कि जब युवक-युवतियां आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे तो कई स्थानीय समस्याओं और बेरोजगारी का स्थायी समाधान संभव होगा। अध्यक्षीय वक्तव्य में असम उन्नति सभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष डंबरु कलिता ने कहा कि नई पीढ़ी को संस्थापन की राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी

है। उन्होंने कृषि आधारित उपक्रमों पर जोर देते हुए बकरी पालन, कुकुरा फार्म, बागवानी और केले की खेती, चारा-कृषि जैसे क्षेत्रों में युवाओं को सहयोग और प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया। उनके अनुसार इसी से खेत और बाजार पर स्थानीय नियंत्रण हासिल किया जा सकता है। सभा में सदौं कामरूप जिला छात्र संस्था के प्रभारी अध्यक्ष सुरजीत कलिता ने कहा कि छात्र संथा और उन्नति सभा मिलकर कृषि क्रांति को बढ़ावा देंगी।

बारिश और भूस्खलन के बीच बदरपुर-सिलचर रेल सेवाएं सामान्य

सिलचर (हिंस)। असम समेत पूरे पूर्वोत्तर राज्य में लगातार भारी बारिश, तूफान तथा भूस्खलन की घटनाएं हो रही है। इसी सिलसिले में सिलचर बदरपुर रेलखंड पर भी कई स्थानों पर भूस्खलन होने की सूचना है। हालांकि, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने शनिवार को जानकारी दी कि भूस्खलन के कारण इस खंड पर रेल सेवा प्रभावित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बदरपुर-सिलचर रेलखंड में फिलहाल बारिश या भूस्खलन के कारण किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है और सभी ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।

नुमलीगढ़ के स्कूल में घुसा जंगली हाथी, की तोड़फोड़

गोलाघाट (हिंस)। असम के नुमलीगढ़ क्षेत्र में जंगली हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि तड़के एक जंगली हाथी 4 नंबर रंगबंग एलपी स्कूल परिसर में घुस आया और स्कूल के कार्यालय कक्ष में जमकर तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों के अनुसार हाथी ने विद्यालय के फर्नीचर और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद इलाके में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। डर के माहौल के चलते छात्र-छात्राएं विद्यालय नहीं आए। हाथियों के लगातार विचरण के कारण अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की मांग की है ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके।

गुवाहाटी में एथेना ने पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एकीकृत मनोरोग अस्पताल खोला

गुवाहाटी। एथेना बिहेवियरल हेल्थ ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े एकीकृत निजी मनोरोग अस्पताल के शुभारंभ की घोषणा की है। इसके साथ ही संगठन का विस्तार देशभर में पांच अस्पतालों तक पहुंच गया है। यह लांच ऐसे समय में हुआ है जब इस क्षेत्र में इसकी बेहद आवश्यकता महसूस की जा रही है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे (एनएमएचएस) के अनुसार, असम की लगभग 8 प्रतिशत आबादी, यानी हर 12 में से करीब 1 व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से प्रभावित है। क्षेत्रीय अध्ययनों में अवसाद, चिंता, नशे की लत से जुड़ी समस्याओं और आत्महत्या से संबंधित तनाव के मामलों में बढ़ोतरी की ओर भी संकेत दिया गया है। इसके साथ ही, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में संगठित मनोरोग और नशामुक्ति उपचार अवसंरचना की गंभीर कमी भी सामने आई है। वर्ष 2021 में गुरुग्राम में एक अस्पताल के साथ स्थापित एथेना बिहेवियरल हेल्थ

ने तेजी से विस्तार करते हुए खुद को बहु-शहरी मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्ति उपचार नेटवर्क के रूप में विकसित किया है। यह संगठन ऐसे क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित और चिकित्सकीय रूप से संचालित विकल्प के रूप में उभरा है, जहां उपचार सेवाएं अक्सर बिखरी हुई और असंगठित मानी जाती हैं। एथेना बिहेवियरल हेल्थ की संस्थापक और सीईओ डॉ. श्रद्धा मलिक ने कहा कि गुवाहाटी में एथेना का विस्तार भारत में उच्च गुणवत्ता वाली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। 2021 में गुरुग्राम से शुरुआत कर पांच केंद्रों का नेटवर्क विकसित करने तक, हमारा फोकस हमेशा संरचित, नैतिक और परिणाम-आधारित उपचार सेवाएं प्रदान करने पर रहा है। गुवाहाटी, इन सेवाओं को कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गुवाहाटी स्थित यह अस्पताल एक ही छत के नीचे मानसिक रोगों और नशे की लत से जुड़ी समस्याओं के लिए समग्र उपचार उपलब्ध कराएगा। इसमें मनोरोग उपचार, मनोचिकित्सा (साइकोथेरेपी), डिटॉक्सिफिकेशन सहायता, पुनर्वास और दीर्घकालिक रिकवरी योजना जैसी सेवाएं शामिल होंगी। यह केंद्र शराब और अन्य नशे की लत, अवसाद, चिंता, आघात (ट्रॉमा) तथा साथ-साथ होने वाली मानसिक बीमारियों जैसी समस्याओं का उपचार करेगा।

होजाई में भव्य रूप से मनाई गई श्री शनि जयंती

होजाई (निसं)। होजाई जिले के ठाकुरबाड़ी रोड स्थित श्री शनि मंदिर में आज भव्य श्री शनि जयंती उत्सव संपन्न हुआ। पावन अवसर पर मंदिर परिसर को फूलों और गुब्बारों से सुसज्जित किया गया था, जिससे स्थल की शोभा बढ़ी। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रात: 5 बजे शांति-पाठ के साथ हुआ। तत्पश्चात शनिदेव का महास्नान और सरसों तेल से तैलाभिषेक कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने अनुशासित ढंग से कतार लगाकर तैलाभिषेक किया और शनि देव के जयघोष व मंत्रों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। तैलाभिषेक के उपरांत भगवान शनि का श्रृंगार किया गया और दोपहर की आरती संपन्न हुई। अपराह्न 3-30 बजे से श्री शनि चालीसा का पाठ हुआ। सांयकाल

में महाआरती व पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने अपने परिवारों के सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आरती के बाद महाप्रसाद वितरित किया गया। मंदिर व्यवस्थापन ने बताया कि इस अवसर पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति भारी रही और सभी धार्मिक कार्यक्रम अनुशासन तथा शांति के साथ सम्पन्न हुए। स्थानीयों व श्रद्धालुओं ने आयोजन की व्यवस्था व भव्यता की प्रशंसा की।

संपादकीय

थोक में महंगाई

अप्रैल माह में थोक महंगाई दर 8.30 फीसदी हो गई, जो मार्च में 3.88 फीसदी थी। बीते 42 माह में यह महंगाई का उच्चतम स्तर है। विशेषज्ञों का मानना है कि मई की महंगाई दर 9 फीसदी को पार कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकतम महंगाई की जो सीमा तय कर रखी है, उसके मुताबिक मुद्रास्फीति 6 फीसदी से नीचे रहनी चाहिए, लेकिन अब आसार 9-10 फीसदी के बन रहे हैं। यकीनन अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। वित्तीय, राजकोषीय और चालू खाता घाटे बढ़ सकते हैं। औसत उपभोक्ता के लिए ईएमआई और ब्याज दरों का बोझ बढ़ेगा। जिस देश के नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल साइकिल, बुलेट, ई-रिक्शा, रेल पर सवार दिख रहे हों और देश के आर्थिक संकट का 'मजाक' बना रहे हों, प्रधानमंत्री के आह्वान का अपमान कर रहे हों, उनके लिए महंगाई कोई चिंतित मुद्दा नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए मरने-जीने का सवाल है। नेतागण 'नौटंकी' करना छोड़ दें, क्योंकि उनकी गतिविधियों से संकट हल होने वाला नहीं है। यदि सुरक्षा कोई संवेदनशील मुद्दा नहीं है और संकट विकराल है, तो मंत्रीगण पैदल चलें। ये दृश्य हास्यास्पद हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी इसे दहशत और चिंता की बात नहीं मानते। बहरहाल यह महंगाई सिर्फ ईरान युद्ध की देन नहीं है। बेशक कच्चे तेल के बढ़ते दाम भी महत्त्वपूर्ण कारक हैं, लेकिन कुछ और विसंगतियां भी हैं, जिनके कारण थोक महंगाई दर इतनी बढ़ी है। यदि थोक महंगाई की स्थिति यह है, तो अंततः खुदरा महंगाई दर भी अपनी मानक सीमा तोड़ कर बढ़ सकती है। नतीजतन आम आदमी की जेब ही कटेगी। देश की 90 फीसदी से अधिक कामगार जमात असंगठित है। उसमें मजदूर, किसान भी, दिहाड़ीदार, अस्थायी ठेकों पर काम करने वाले और असंख्य बाल-मजदूर आदि शामिल हैं। जो जमात औसतन 10-12 हजार रुपए महीना ही कमा पाती है, उसके घर में 3000-3500 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर कैसे खरीदा जा सकता है? कालाबाजारी में सिलेंडर इसी दाम पर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। सरकारी संरक्षण के बिना 'कालाबाजार' चल ही नहीं सकता? यह व्यापक शोध का विषय है। इससे 'उज्ज्वला' की विसंगतियां भी बेनकाब होंगी। कहां है युद्ध और ऊर्जा का संकट? गैस का बड़ा सिलेंडर 1300 रुपए महंगा हो चुका है। आयातित दालें 35 फीसदी, खाद्य तेल 15 रुपए, मेवे 80 फीसदी, दूध 2-5 रुपए प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। चावल, चीनी, आटा, गेहूं, अंडा, मांस, मछली आदि भी महंगे बिक रहे हैं। सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक क्यों लगाई है? निर्यात तो पहले ही बिखर चुका है। बेशक प्याज, टमाटर, आलू की कीमतें शांत हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के उत्पाद 4.62 फीसदी महंगे हुए हैं। इस क्षेत्र की बाजार में 64 फीसदी हिस्सेदारी है और सूक्ष्म स्तर पर सर्वाधिक रोजगार भी इसी क्षेत्र में है। मुंबई में सीएनजी 2 रुपए महंगी कर दी गई है, जहां 12 लाख से अधिक वाहन सीएनजी इस्तेमाल करते हैं। अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि आम आदमी के लिए महंगाई दर 8-9 फीसदी नहीं, बल्कि 30-40 फीसदी है, क्योंकि उसकी आमदनी बेहद सीमित है और वह 'कालाबाजार' का शिकार है। इस संदर्भ में भी रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आगाह किया है कि यदि मध्य-पूर्व का संकट नहीं थमा, तो महंगाई और बढ़ेगी। तेल-गैस और खाद की किल्लत बढ़ेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार कुछ छिपा रही है, क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई 'करिश्मा' नहीं है कि वह ईरान युद्ध से बेअसर रह सके। लंबे वक्त तक पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम न बढ़ाए जाएं। सरकार और तेल कंपनियां कब तक घाटा झेलती रहेंगी। देश पर पहले से ही 200 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। बहरहाल आजकल सोने की खूब चर्चा है। वैसे यह भी महंगाई का हिस्सा है और 10 ग्राम सोने के दाम 1.55 लाख रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। एक रपट सामने आई थी कि भारत में घरों के पास 710 किग्रा सोना है। उन्होंने पैसा और कुछ पेशकश के बावजूद सोना सरकार को नहीं सौंपा। यह भी अनुमान है कि भारत में मंदिरों, मठों, घरों में करीब 50,000 टन सोना रखा है। यह 830 लाख करोड़ का आंका गया है। यदि सरकार गंभीर है, तो इस सोने का अधिग्रहण करे। कई संकट हल हो सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकतम महंगाई की जो सीमा तय कर रखी है, उसके मुताबिक मुद्रास्फीति 6 फीसदी से नीचे रहनी चाहिए, लेकिन अब आसार 9-10 फीसदी के बन रहे हैं। यकीनन अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। वित्तीय, राजकोषीय और चालू खाता घाटे बढ़ सकते हैं। औसत उपभोक्ता के लिए ईएमआई और ब्याज दरों का बोझ बढ़ेगा। जिस देश के नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल साइकिल, बुलेट, ई-रिक्शा, रेल पर सवार दिख रहे हों और देश के आर्थिक संकट का 'मजाक' बना रहे हों, प्रधानमंत्री के आह्वान का अपमान कर रहे हों, उनके लिए महंगाई कोई चिंतित मुद्दा नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए मरने-जीने का सवाल है। नेतागण 'नौटंकी' करना छोड़ दें, क्योंकि उनकी गतिविधियों से संकट हल होने वाला नहीं है। यदि सुरक्षा कोई संवेदनशील मुद्दा नहीं है और संकट विकराल है, तो मंत्रीगण पैदल चलें। ये दृश्य हास्यास्पद हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी इसे दहशत और चिंता की बात नहीं मानते। बहरहाल यह महंगाई सिर्फ ईरान युद्ध की देन नहीं है।

घरों में बेटियों पर नियंत्रण और बेटों को छूट देने वाली मानसिकता आज भी कायम है

कब तक दोहराई जाती रहेंगी निर्भया जैसी त्रासदियां?

दिल्ली के नांगलोई में एक निजी बस के भीतर महिला के साथ हुई बस कंडक्टर एवं ड्राइवर के दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया है। यह घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि उस भयावह सामाजिक और प्रशासनिक विफलता का आईना है, जो वर्षों से हमारे सामने खड़ी है। चौदह वर्ष पहले निर्भया कांड के बाद देश की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा था। लोगों ने सोचा था कि अब व्यवस्था बदलेगी, कानून सख्त होंगे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और समाज अपनी सोच बदलेगा। लेकिन आज जब उसी प्रकार की घटनाएं पुनः पुनः सामने आती हैं, तब यह प्रश्न और भी तीखा होकर उठता है कि आखिर हम बदले कहां हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार-बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसका उत्तर केवल कानून की कमजोरी में नहीं, बल्कि समाज की उस विकृत मानसिकता में छिपा है, जहां महिला को आज भी बराबरी के सम्मान के साथ नहीं देखा जाता। आधुनिकता के चमकदार दावों के बीच भी पुरुष प्रधान सोच का अंधेरा जस का तस मौजूद है। महिलाओं को व्यक्ति नहीं, बल्कि उपभोग की वस्तु मानने वाली सोच आज भी अनेक मन-मस्तिष्कों में गहराई तक बैठी हुई है। यही कारण है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, स्कूल-कॉलेजों और यहां तक कि घरों के भीतर भी महिलाएं असुरक्षा का अनुभव करती हैं। विडंबना यह है कि विज्ञान, तकनीक और आर्थिक विकास के इस दौर में भी समाज स्त्री के सम्मान और सुरक्षा के बुनियादी संस्कार विकसित नहीं कर पाया। बच्चों को शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन संवेदनाएं नहीं दी जा रहीं। घरों में बेटियों पर नियंत्रण और बेटों को छूट देने वाली मानसिकता आज भी कायम है। एक ओर लड़कियों को "सावधान रहने" की नसीहत दी जाती है, दूसरी ओर लड़कों को अपने व्यवहार और दृष्टि की मर्यादा सिखाने की गंभीर कोशिश बहुत कम दिखाई देती है। यही असंतुलन आगे चलकर अपराधों की जमीन तैयार करता है। प्रश्न यह भी है कि प्रशासन बार-बार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम क्यों हो रहा है? निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे। सीसीटीवी कैमरे, महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुलिस गश्त और सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा उपायों की लंबी घोषणाएं हुईं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन व्यवस्थाओं का बड़ा हिस्सा कागजों और भाषणों तक सीमित रह गया। निजी बसें आज भी बिना पर्याप्त निगरानी के चल रही हैं। कई स्थानों पर चालक और परिचालकों का समुचित सत्यापन तक नहीं होता। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन अक्सर केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। दुनियाभर में बालिकाओं के अस्तित्व एवं अस्मिता के लिये जागरूकता एवं आन्दोलनों के बावजूद बालिकाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है, बालिकाओं की स्थिति, लड़कियों की तुलना में लड़कों की बढ़ती संख्या, तलाक के बढ़ते मामले, गांवों में

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और समाज अपनी सोच बदलेगा। लेकिन आज जब उसी प्रकार की घटनाएं पुनः पुनः सामने आती हैं, तब यह प्रश्न और भी तीखा होकर उठता है कि आखिर हम बदले कहां हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार-बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसका उत्तर केवल कानून की कमजोरी में नहीं, बल्कि समाज की उस विकृत मानसिकता में छिपा है, जहां महिला को आज भी बराबरी के सम्मान के साथ नहीं देखा जाता। आधुनिकता के चमकदार दावों के बीच भी पुरुष प्रधान सोच का अंधेरा जस का तस मौजूद है। महिलाओं को व्यक्ति नहीं, बल्कि उपभोग की वस्तु मानने वाली सोच आज भी अनेक मन-मस्तिष्कों में गहराई तक बैठी हुई है। यही कारण है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, स्कूल-कॉलेजों और यहां तक कि घरों के भीतर भी महिलाएं असुरक्षा का अनुभव करती हैं। विडंबना यह है कि विज्ञान, तकनीक और आर्थिक विकास के इस दौर में भी समाज स्त्री के सम्मान और सुरक्षा के बुनियादी संस्कार विकसित नहीं कर पाया।

बालिका की अशिक्षा, कुपोषण एवं शोषण, बालिकाओं की सुरक्षा, बालिकाओं के साथ होने वाली बलात्कार की घटनाएं, अश्लील हरकतें और विशेष रूप से उनके खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्रभावी चर्चा एवं कठोर निर्णयों से एक सार्थक वातावरण का निर्माण किये जाने की अपेक्षा है। क्योंकि एक टीस-सी मन में उठती है कि आखिर महिलाएं एवं बालिकाओं कब तक भोग की वस्तु बनी रहेगी? उसका जीवन कब तक खतरों से घिरा रहेगा? बलात्कार, छेड़खानी, भ्रूण हत्या और दहेज की धधकती आग में वह कब तक भस्म होती रहेगी? कब तक उसके अस्तित्व एवं अस्मिता को नौचा जाता रहेगा? सच्चाई यह है कि हमारी व्यवस्था अपराध होने के बाद सक्रिय होती है, अपराध रोकने के लिये नहीं। हर बार घटना के बाद गिरफ्तारी, जांच और बयानबाजी होती है, लेकिन अपराध की जड़ों तक पहुंचने की गंभीर पहल नहीं दिखाई देती। राजनीतिक दल कुछ दिनों तक आरोप-प्रत्यारोप करते हैं, मीडिया में बहस चलती है और फिर धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य मान लिया जाता है। लेकिन जिन परिवारों की बेटियां इस अमानवीयता का शिकार होती हैं, उनके जीवन में भय, पीड़ा और असुरक्षा स्थायी घाव बनकर रह जाते हैं। यह भी विचारणीय है कि आखिर महिलाएं और बालिकाएं बार-बार ऐसे अत्याचारों का शिकार क्यों बन रही हैं? इसका कारण केवल अपराधियों की क्रूरता नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता भी है। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सामूहिक जिम्मेदारी का अभाव दिखाई देता है। लोग तमाशबीन बन जाते हैं। कई बार पीड़िता को ही कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है-उसके कपड़े, समय, जीवनशैली और व्यवहार पर सवाल उठाए जाते हैं। यह मानसिकता अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समाज पूरी तरह पीड़िता के साथ खड़ा नहीं होगा। कब तक महिलाएं अपने ही शहरों, बसों, गलियों और कार्यस्थलों पर भय के साथ जीती रहेंगी? कब तक माता-पिता अपनी बेटियों के घर लौटने तक चिंता में डूबे रहेंगे? यह प्रश्न केवल महिलाओं का नहीं, बल्कि पूरे समाज की आत्मा का प्रश्न है। जिस समाज में आधी आबादी स्वयं को सुरक्षित महसूस न करे, वह समाज वास्तव में सभ्य नहीं कहलाया जा सकता। आज आवश्यकता केवल कठोर कानूनों की नहीं, बल्कि कठोर सामाजिक आत्ममंथन की है। कानून अपराधी को दंड दे सकता है, लेकिन समाज ही मानसिकता बदल सकता है। स्कूलों और परिवारों में लैंगिक संवेदनशीलता की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। बेटियों को भय में जीना नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक जीना सिखाना होगा। फिल्मों, सोशल मीडिया और विज्ञापनों में स्त्री की वस्तुवादी छवि पर भी गंभीर विमर्श जरूरी है, क्योंकि संस्कृति और मनोरंजन भी समाज की सोच को प्रभावित करते हैं। प्रशासन को भी केवल घटनाओं के बाद की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन में रियल-टाइम जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन और नियमित निगरानी को पूरी कठोरता से लागू करना होगा। निजी परिवहन संचालकों और कर्मचारियों का गहन सत्यापन अनिवार्य किया जाना चाहिए। पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और सक्रिय बनाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि समाज को यह समझना होगा कि महिला सुरक्षा कोई "महिला मुद्दा" नहीं, बल्कि मानवता और सभ्यता का प्रश्न है। जब तक स्त्री को समान सम्मान, स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक विकास के सारे दावे अधूरे रहेंगे। नांगलोई की यह घटना केवल एक समाचार नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। यदि अब भी हम नहीं जागे, तो निर्भया जैसी त्रासदियां बार-बार हमारे सामने आती रहेंगी और हर बार हमारी संवेदनहीनता, हमारी प्रशासनिक विफलता और हमारी विकृत मानसिकता हमें कठघरे में खड़ा करती रहेगी। प्रश्न यही है-आखिर कब तक? तमाम जागरूकता एवं सरकारी प्रयासों के बावजूद भारत में भी बालिकाओं की स्थिति में यथोचित बदलाव नहीं आया है। धर्मगुरु, राजनेता एवं समाजसुधारक महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति कितनी कुत्सित मानसिकता का परिचय देते आए हैं, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। इनके चरित्र का दोहरापन जगजाहिर हो चुका है। कोई क्या पहने, क्या खाए, किससे प्रेम करे और किससे शादी करें, सह-शिक्षा का विरोधी नजरिया- इस तरह की पुरुषवादी सोच के तहत बालिकाओं को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, उन पर तरह-तरह की बंदिशें एवं पहरे लगाये जा रहे हैं। 'यत्र पूज्यंते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता'- जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। किंतु आज हम देखते हैं कि नारी का हर जगह अपमान होता चला जा रहा है। उसे 'भोग की वस्तु' समझकर आदमी 'अपने तरीके' से 'इस्तेमाल' कर रहा है, यह बेहद चिंताजनक बात है। आज अनेक शक्लों में नारी के वजूद को धुंधलाने की घटनाएं शक्ल बदल-बदल कर काले अध्याय रच रही हैं। देश में गैंग रेप की वारदातों में कमी भले ही आयी हो, लेकिन उन घटनाओं का रह-रह कर सामने आना त्रासद एवं दुःखद है।

देश | दुनीया से

न्याय का चश्मा और पुरुष पीड़ा का मौन प्रतिवाद

जीवन हारने के लिए नहीं, बल्कि हक के लिए लड़ने के लिए है। हमारे समाज में 'मर्दानगी' की खोखली परिभाषा और 'मर्दों को दर्द नहीं होता' जैसे संवादों ने पुरुषों के चारों ओर चुप्पी की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है, जहां उनका मानसिक संताप सिसकियों में भी नहीं बदल पाता। अक्सर वैवाहिक प्रताड़ना और 'लोकलाज' के डर से पुरुष खामोशी या आत्मघाती कदम चुन लेता है। आज समय की मांग है कि हम पुरुष मानसिक उत्पीड़न को केवल एक निजी व्यथा न मानकर, इसे एक गंभीर कानूनी और मनोवैज्ञानिक संकट के रूप में स्वीकार करें। युवा जज अमन शर्मा की आत्महत्या ने न्याय व्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है, जो यह सिद्ध करता है कि पद और प्रतिष्ठा मानसिक प्रताड़ना के आगे बौने हैं। जब दूसरों को न्याय दिलाने वाला कानून का ज्ञाता स्वयं को इतना असुरक्षित और असहाय पाकर मौत को गले लगा लेता है, तो यह हमारे तंत्र की गंभीर विफलता को दर्शाता है। विशेषकर 'लव मैरिज' जैसे रिश्तों में पुरुष अक्सर उस दोहरे नैतिक दबाव और 'अपनों के खिलाफ चुनाव' के बोझ तले दब जाता है, जहां प्रताड़ना सहते हुए भी उसे घर वापसी के रास्ते बंद नजर आते हैं। यह प्रकरण एक भयावह चेतावनी है कि मानसिक यंत्रणा चरम पर होने पर ज्ञान और पद पीछे छूट जाते हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि कानून को 'जेंडर' के बजाय 'पीड़ा' के चश्मे से देखा जाए। वर्तमान में सामाजिक और कानूनी ढांचे में जहां महिलाओं के लिए कठोर सुरक्षा तंत्र मौजूद है, वहीं पीड़ित पुरुषों के प्रति अक्सर उदासीनता देखी जाती है। विशेष रूप से धारा 498ए के दुरुपयोग को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ (2005) के मामले में 'कानूनी आतंकवाद' की संज्ञा दी है। इसका मुख्य कारण यह है कि पतियों के पास पत्नी द्वारा की गई शारीरिक हिंसा या घर से निकाले जाने की स्थिति में वैसी त्वरित वैधानिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद, बदलती न्यायिक चेतना अब 'मानसिक क्रूरता' के आधार पर पुरुषों को राहत प्रदान कर रही है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(आईए) के तहत निरंतर अपमान और प्रताड़ना को तलाक का वैध आधार माना गया है, जबकि धारा 10 के अंतर्गत 'न्यायिक पृथक्करण' मानसिक शांति के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झूठे मुकदमों और ब्लैकमेलिंग के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 182 एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है, जिससे पुरुष कानूनी बारीकियों का उपयोग कर अपनी गरिमा और अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। भारतीय न्यायपालिका ने अपने विभिन्न निर्णयों, विशेषकर नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006) और समर घोष बनाम जया घोष (2007) के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कानून का उद्देश्य केवल किताबी प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा करना भी है। इन ऐतिहासिक फैसलों ने 'मानसिक क्रूरता' के दायरे को विस्तार देते हुए माना कि यदि वैवाहिक रिश्ता पूरी तरह टूट चुका हो और पति पर वृद्ध माता-पिता को छोड़ने का दबाव बनाना या उसे संतान के सुख से वंचित करना जैसी असहनीय स्थितियां उत्पन्न हों, तो उसे इस बोझिल बंधन से मुक्त होने का पूरा अधिकार है। यह न्यायिक दृष्टिकोण रेखांकित करता है कि न्याय के तराजू में संवेदनशीलता और यथार्थवाद का संतुलन अनिवार्य है, जहां व्यक्ति की मानसिक शांति को वैधानिक औपचारिकताओं से ऊपर स्थान दिया गया है। विकसित देशों में पुरुष उत्पीड़न को लेकर कानून अधिक संतुलित हैं। यूनाइटेड किंगडम में जबरन नियंत्रण का कानून जेंडर न्यूट्रल है, जो यह स्वीकार करता है कि पुरुष भी भावनात्मक शोषण के शिकार हो सकते हैं। अमेरिका, कनाडा और स्कैंडिनेवियन देशों में पुरुषों के लिए विशेष 'एब्यूज शेल्टर' और हेल्पलाइन सक्रिय हैं। भारत में भी अब समय आ गया है कि हम अपनी कानूनी धाराओं को जेंडर न्यूट्रल बनाने की दिशा में विचार करें, ताकि न्याय का तराजू किसी एक तरफ न झुके। व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए केवल कानूनों का संकलन मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए धरातल पर एक नई सोच और व्यावहारिक दृष्टिकोण के सूत्रपात की आवश्यकता है। सबसे पहले, हमें संवाद और सामाजिक साहस को बढ़ावा देना होगा ताकि समाज में व्याप्त इस धारणा को बदला जा सके कि अपनी समस्या साझा करना कमजोरी की निशानी है। 'लोग क्या कहेंगे' के डर से ऊपर उठकर यह समझना अनिवार्य है कि आपका जीवन किसी भी सामाजिक लोकलाज से कहीं अधिक कीमती है; यदि कोई रिश्ता बोझ बन जाए, तो उसे घुट-घुटकर ढोने के बजाय सम्मानजनक अलगाव का साहस जुटाना ही बेहतर है। डिजिटल युग में मौन को अपनी नियति बनाने के बजाय न्याय को अपना मार्ग चुनिए; याद रखिए, आपका जीवन और आत्म-सम्मान किसी भी सामाजिक लोकलाज से कहीं अधिक कीमती है। पूर्वाग्रह मुक्त जांच की नितांत आवश्यकता है। साक्ष्य संचयन केवल कानूनी हथियार नहीं, बल्कि आपकी सच्चाई का प्रमाण है। पुरुषों को मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 'मेंस वेलफेयर' संस्थाओं और मनोवैज्ञानिकों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आप का | नजरीया

चुनाव तू फिर आना

नगर निगम चुनाव की हसरतों में राजनीति ने यह बता दिया कि आइंदा इस सफर की ओट में विकास की परिभाषा बदलेगी। विजन जिस तरह स्थानीय मुद्दों से सभी के आचरण तक पहुंचा, उससे स्वाभाविक तौर पर अंतर आएगा। चार नगर निगमों के बहाने आम नागरिक यह समझ सकता है कि चुनाव में टिके रहने के लिए राजनीति को अपने दूत सही करने पड़ेंगे। अफसोस यह कि पार्षदों से मेयर और मेयर बनने की मेहरबानियों से ये शहर गफलत में हैं, लेकिन शहरी चरित्र और जवाबदेही के विषय घूम फिर कर वापस आ गए। संकल्पों से हटकर राजनीति ने तू-तू, मैं-मैं की रट में एक लाजिमी बहस से किनारा किया और बीच-बीच में लगने लगा कि भाजपा सत्ता को कोस रही और कांग्रेस दिल्ली की सत्ता को कोस रही है। अगर चुनाव पारंपरिक राजनीति में उछलते वैमनस्य पर ही होने हैं, तो हम शहरी व्यवस्था को समझ ही नहीं रहे। यह दीगर है कि पार्टियों ने कुछ शहरी बिंदुओं पर चुनाव की फेहरिस्त बनाई है, लेकिन राज्य के लिए यह द्वार पूरी तरह नहीं खुला। कांग्रेस ने अपने विजन की वकालत में चारों शहरों को अपनी उमंगों से जोडने का मंतव्य समझाया। बेहतर होता सत्ता दल इस बहाने हिमाचल के शहरीकरण को संबोधित करता यानी पूरे प्रदेश के शहरों में अगले दशक में क्या तस्वीर होगी। कौन से व्यवस्थागत व ढांचागत परिवर्तन अहम होते। स्थानीय परिवहन या लोकल ट्रांसपोर्ट पर बहुत सा कार्य संभव है। जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति के नक्शे पर शहरीकरण की नई परिभाषा क्या होगी। बेशक नगर निगम चुनावों में हौले से कुछ ऐसे मुद्दे या संकल्प आए हैं, जो शहर को नई दृष्टि से देख रहे हैं। मसलन पर्यटन ने ऊंची आवाज देकर चुनाव से कहा है, 'मैं यहां हूं।' पालमपुर में 'पर्यटन सर्किट' खोजती भाजपा ने एक हुंकार भरा है, तो मंडी का शिवधाम और मंदिर प्रदक्षिणा के करीब चुनाव ने संभावना देखी है। सोलन की कसौटियां अभी भी नहीं समझीं कि महानगर बनने की आभा को बचाने की कितनी जरूरत है। कांग्रेस और भाजपा के घोषणा पत्रों का एक बड़ा युद्ध धर्मशाला में देखा गया। वादे सफेद चादर पर लिखे दाग हो जाएं, तो कौन अपनी चैन को मुगालते में देखेगा। यह इसलिए कि हर पार्टी और पार्टियों की हर सरकार ने शहरों को सियासत का मुर्गा बना दिया। राजनीति प्रभाव से कई सिंह द्वार अगर किसी विधानसभा क्षेत्र की पहचान हैं, तो यह कारनामा सिर्फ प्रचार है। प्रतीक और चिन्ह ढूंढते नेताओं ने हिमाचल की समग्रता को समझा ही नहीं। हर शहर अगर एक आर्थिक केंद्र तथा रोजगार का मंच है, तो विकास की योजनाएं इस आधार को आकार देतीं। हिमाचल के कई कस्बे व शहर अपने वजूद में, पर्यटन की मौलिकता के साथ हाजिर हैं, तो इनका विकास इसी लिहाज से होना चाहिए। कुछ शहर शिक्षा के हब बन रहे हैं, तो कुछ खेल गतिविधियों के केंद्र। कुछ युवा पर्यटकों के आकर्षण में फल फूल रहे, तो कई अन्य आयोजन के कारण मशहूर हैं। किसी शहर के नक्षत्र वहां के मंदिर तय कर रहे हैं, तो योजना अलग-अलग प्रारूप में होनी चाहिएं। क्या चुनाव के बाद मंडी को हम सांस्कृतिक राजधानी की क्षमता में खड़ा कर पाएंगे। क्या पालमपुर अपने परिवेश में चाय के बागीचों के संतुलन से 'पर्यटन सर्किट' का इतिहास लिखेगा। क्या सोलन अपनी रफ्तार को चंडीगढ़-शिमला के बीच साझा कर पाएगा। इसी फेहरिस्त में सबसे अधिक तखल्लुस ओढने वाला मिनी ल्हासा, शीत कालीन राजधानी, खेल नगरी, इवेंट नगरी और स्मार्ट सिटी का खिताब धारण किए हुए धर्मशाला से किए गए वादे निभाए जाएंगे। सुनने में चुनाव बहुत अच्छे लगते हैं। नेताओं के मिजाज बहुत अच्छे लगते हैं, मगर फिर शहरी हालात अगले चुनाव तक अपनी इच्छाओं का पिटारा उठाए रहते हैं।

चार नगर निगमों के बहाने आम नागरिक यह समझ सकता है कि चुनाव में टिके रहने के लिए राजनीति को अपने दूत सही करने पड़ेंगे। अफसोस यह कि पार्षदों से मेयर और मेयर बनने की मेहरबानियों से ये शहर गफलत में हैं, लेकिन शहरी चरित्र और जवाबदेही के विषय घूम फिर कर वापस आ गए। संकल्पों से हटकर राजनीति ने तू-तू, मैं-मैं की रट में एक लाजिमी बहस से किनारा किया और बीच-बीच में लगने लगा कि भाजपा सत्ता को कोस रही और कांग्रेस दिल्ली की सत्ता को कोस रही है। अगर चुनाव पारंपरिक राजनीति में उछलते वैमनस्य पर ही होने हैं, तो हम शहरी व्यवस्था को समझ ही नहीं रहे। यह दीगर है कि पार्टियों ने कुछ शहरी बिंदुओं पर चुनाव की फेहरिस्त बनाई है, लेकिन राज्य के लिए यह द्वार पूरी तरह नहीं खुला। कांग्रेस ने अपने विजन की वकालत में चारों शहरों को अपनी उमंगों से जोडने का मंतव्य समझाया। बेहतर होता सत्ता दल इस बहाने हिमाचल के शहरीकरण को संबोधित करता यानी पूरे प्रदेश के शहरों में अगले दशक में क्या तस्वीर होगी। कौन से व्यवस्थागत व ढांचागत परिवर्तन अहम होते। स्थानीय परिवहन या लोकल ट्रांसपोर्ट पर बहुत सा कार्य संभव है। जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति के नक्शे पर शहरीकरण की नई परिभाषा क्या होगी। बेशक नगर निगम चुनावों में हौले से कुछ ऐसे मुद्दे या संकल्प आए हैं, जो शहर को नई दृष्टि से देख रहे हैं। मसलन पर्यटन ने ऊंची आवाज देकर चुनाव से कहा है, 'मैं यहां हूं।' पालमपुर में 'पर्यटन सर्किट' खोजती भाजपा ने एक हुंकार भरा है, तो मंडी का शिवधाम और मंदिर प्रदक्षिणा के करीब चुनाव ने संभावना देखी है।

कुछ | अलग

ईमानदार प्रयास में सफलता

एक युवा लेखक ने अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे से पूछा कि वह लिखना तो चाहता है, पर उसे शुरुआत करने में ही डर लगता है कि शब्द अच्छे नहीं होंगे। हेमिंग्वे ने उसे सलाह दी कि वह हर दिन केवल एक सच्चा वाक्य लिखे—ऐसा वाक्य जो पूरी ईमानदारी से उसके अनुभव या विचार को व्यक्त करे। युवक को यह बहुत सरल लगा, पर जब उसने प्रयास किया, तो उसे महसूस हुआ कि सच्चा और स्पष्ट लिखना उतना आसान नहीं है। कुछ दिनों बाद उसने पाया कि उसके वाक्य अधिक सटीक और प्रभावी होने लगे हैं। तब हेमिंग्वे ने कहा, 'महान लेखन जटिल शब्दों से नहीं, सच्चाई से शुरू होता है।' उन्होंने समझाया कि यदि आधार ईमानदार हो, तो बाकी रचना उसी पर विकसित हो जाती है।

दृष्टि | कोण

हाल के चुनावों में संसदीय व्यवस्था के खतरे

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए हालिया चुनावों ने एक बार फिर भारत की संसदीय व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इन चुनावों ने दिखाया कि किस प्रकार चुनावों में हेरफेर किया जा सकता है, अलोकतांत्रिक तरीकों से सरकारें बनाई जा सकती हैं, गठबंधन अस्थिर हो सकते हैं, और भारी बहुमत वाली सरकारें तानाशाही प्रवृत्ति अपना सकती हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये अलग-अलग विफलताएं नहीं हैं, बल्कि ऐसी संरचनात्मक खामियां हैं जिनका संसदीय व्यवस्था में कोई वास्तविक समाधान नहीं है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को करारी हार दी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया स्वयं अत्यंत विवादास्पद रही। मतदान से कुछ ही सप्ताह पहले, भारत के चुनाव आयोग- जो भाजपा-नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है- ने लगभग 12 फीसदी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए। विश्लेषकों का तर्क है कि यह संख्या राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 99 सीटों पर भाजपा की जीत के अंतर से अधिक थी। ऐसी हेरफेर लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि इससे एक-दलीय प्रभुत्व का रास्ता खुलता है। फिर भी चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूचियों में संशोधन करने के अपने विशेष संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए अपने कदम का बचाव किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी व्यापक रूप से इस स्थिति का समर्थन किया और कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं, असंतुष्ट नागरिकों को अपील न्यायाधिकरण का सहारा लेना चाहिए। व्यवहार में, हालांकि, भारत की धीमी और महंगी न्याय व्यवस्था ने मताधिकार से वंचित मतदाताओं को चुनाव से पहले कोई प्रभावी राहत नहीं दी। भारत की संसदीय व्यवस्था चुनाव आयोग पर बहुत कम नियंत्रण प्रदान करती है। चूंकि केंद्र में सत्तारूढ़ दल कार्यपालिका और विधायिका दोनों को नियंत्रित करता है, इसलिए प्रधानमंत्री आयोग में नियुक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, प्रशासनिक नियमों को आकार दे सकते हैं, और मतदाता पात्रता से संबंधित कानून बना सकते हैं। तमिलनाडु के चुनावों ने संसदीय व्यवस्था की एक और बार-बार सामने आने वाली खामी को उजागर किया- त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सरकार गठन अक्सर मनमाना और अलोकतांत्रिक बन जाता है। राज्यपाल- जो आमतौर पर केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा नियुक्त होते हैं- के पास यह तय करने का व्यापक विवेकाधिकार होता है कि सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया जाए, क्योंकि संविधान में स्पष्ट प्रक्रिया का अभाव है। तमिलनाडु में, भाजपा समर्थक माने जाने वाले राज्यपाल ने टीवीके के नेता, जिसे बहुमत के लिए आवश्यक 118 में से 108 सीटें मिली थीं, को शपथ दिलाने से पहले ही समर्थन साबित करने के लिए कहा। आलोचकों ने आरोप लगाया कि यह देरी भाजपा को वैकल्पिक गठबंधन तैयार करने का समय देने के उद्देश्य से की गई थी। राज्यपाल पद का राजनीतिकरण लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। इससे केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को पर्दे के पीछे की राजनीति के माध्यम से राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिलता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि दल विधायकों को तोडने के लिए लालच और दबाव का इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण 'रिसॉर्ट राजनीति' जैसा परिचित दृश्य सामने आया है, जिसमें विधायकों को प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए छिपाकर रखा जाता है।

सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी : स्वतंत्र देव सिंह

कानपुर (हिंस)। केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। सेवा, समर्पण और संगठन की भावना के साथ कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह बातें शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहीं। भारतीय जनता पार्टी कानपुर ग्रामीण द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान-2026 के अंतर्गत दो दिवसीय *पंडित दीनदयाल महा प्रशिक्षण* अभियान का शुभारंभ शनिवार को मोतीझील स्थित होटल रॉयल क्लिफ में किया गया। 17 मई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन भाजपा कानपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक उपेन्द्र पासवान की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इसके बाद वंदेमातरम का सामूहिक गायन हुआ।

उद्घाटन सत्र में स्वतंत्र देव सिंह ने *सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं और उनके क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका* विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने *सबका साथ, सबका विकास* के मूल मंत्र के साथ करोड़ों गरीब, वंचित, शोषित और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने और अंतिम व्यक्ति को लाभ दिलाने में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव और शहर-शहर जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना और आवास योजना जैसी योजनाओं में पात्र लोगों का पंजीकरण कराने में भी कार्यकर्ता सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली जमीनी समस्याओं और भ्रष्टाचार की जानकारी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। प्रथम सत्र की प्रस्तावना रखते हुए प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी एवं एमएलसी जीतेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना और कार्यकर्ताओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना ही इस महाभियान का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं के वैचारिक, सामाजिक और संगठनात्मक विकास का माध्यम है। द्वितीय सत्र में क्षेत्रीय महामंत्री रामकिशोर साहू ने *विचार परिवार* विषय पर संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका और राष्ट्र निर्माण में स्वयंसेवकों के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ ने हर संकट के समय समाज सेवा का कार्य किया है और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। तृतीय सत्र में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह ने *कार्य पद्धति* विषय पर कहा कि संगठन की मजबूती अनुशासन, समर्पण और निरंतर जनसंपर्क से संभव है। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। चतुर्थ सत्र में राज्यसभा सांसद एवं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूराम निषाद ने *भाजपा का इतिहास एवं विकास* विषय पर भाजपा की वैचारिक यात्रा और जनसंघ से भाजपा तक के सफर की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिना भेदभाव सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पंचम सत्र में क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी एवं क्षेत्रीय संयोजक सोशल मीडिया महेन्द्र विक्रम सिंह ने *मीडिया प्रबंधन व सोशल मीडिया (एआई)* विषय पर कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी। षष्ठम सत्र में क्षेत्रीय मंत्री पवन प्रताप सिंह ने *व्यावहारिक सत्र* विषय पर कार्यकर्ताओं को सहभागिता आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर जिला प्रभारी राधेश्याम पांडेय, पूर्व जिलाध्यक्ष रवि दीक्षित, रामशरण कटियार, सुशील कटियार, कृष्णमुरारी शुक्ला, दिनेश कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, ब्लॉक प्रमुख इंद्रजीत सिंह, अनुराधा अवस्थी, अशोक सचान, राजेश शुक्ला, अरुण कोरी, शुभम बाजपेई, जिला महामंत्री समरजीत सिंह, जेपी कटियार, वेदव्रत सचान, जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव, जिला मंत्री श्याम सिंह, अंजलि तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी मयंक अवस्थी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

महिला अपराधों पर राजस्थान पुलिस का जीरो टॉलरेंस 5 जिलों के 10 बड़े मामलों में अपराधियों को कड़ी सजा

जयपुर (हिंस)। महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों पर राजस्थान पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए *जीरो टॉलरेंस* नीति के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। महानिदेशक-महानिरीक्षक पुलिस सम्मेलन 2025 की अनुशंसाओं और डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में महिला अत्याचार और पोक्सो एक्ट के गंभीर मामलों में त्वरित अनुसंधान एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई गई है। राजस्थान के पांच जिलों के 10 महत्वपूर्ण मामलों में अदालतों ने दोषियों को आजीवन कारावास, 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और भारी आर्थिक दंड से दंडित किया है। पुलिस प्रशासन इन फैसलों को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से आमजन तक पहुंचा रहा है, ताकि समाज में सुरक्षा का संदेश और अपराधियों में कानून का भय पैदा हो सके। जैसलमेर जिले में नाचना थाना पुलिस ने तीन वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म के मामले में महज 10 दिनों में अनुसंधान पूरा कर 18वें दिन चालान पेश किया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं सांकड़ा थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी पुरुषोत्तम को पोक्सो कोर्ट ने मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई। फलसूंड थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। जालोर जिले में पोक्सो एक्ट के तीन मामलों में अदालत ने दोषियों को 20-20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। झाब थाना पुलिस के एक मामले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा

मिली। दूसरे मामले में स्कूल जा रही नाबालिग का अपहरण कर वीडियो वायरल करने और ब्लैकमेलिंग के आरोपी को भी 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। बागरा थाना क्षेत्र में नाबालिग को भगाने के आरोपी को 20 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया। श्रीगंगानगर जिले में दहेज हत्या के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी राकेश कुमार और सह आरोपी महावीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। धौलपुर जिले के महिला थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सलमान उर्फ लबेदू को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 6500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जयपुर ग्रामीण में गोविंदगढ़ थाना पुलिस के मामले में नाबालिग को होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी विकास कुमार स्वामी को 20 वर्ष की सजा और 1.75 लाख रुपए के भारी जुर्माने से दंडित किया गया। वहीं अमरसर थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी मोहन लाल कुमावत को भी 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

जनसेवा, राष्ट्रवाद और किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है सरकार : श्याम सिंह राणा

कैथल (हिंस)। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है, जिसका लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनसेवा, राष्ट्रवाद और किसानों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित है। शनिवार को कैथल के सूर्यकुंड तीर्थ मंदिर सभागार में पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के शुभारंभ अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने यह बात कही। इससे पूर्व उन्होंने रिबन काटकर कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मंत्री राणा ने बताया कि प्रदेशभर में आयोजित इन प्रशिक्षण शिविरों का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है, ताकि पात्र व्यक्ति इनका पूरा लाभ उठा सकें। साथ ही इन शिविरों के जरिए राष्ट्रवाद की भावना को सुदृढ़ कर देश को और अधिक सशक्त बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों और अन्य वर्गों के उत्थान के लिए लगातार योजनाएं लागू कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री राणा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। फसल बोने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया जाता है और फसलों की खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खातों में ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

नीट पेपर लीक और छात्र की आत्महत्या पर कांग्रेस का प्रदर्शन, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

कानपुर (हिंस)। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर में नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण और लखीमपुर खीरी के छात्र ऋतिक मिश्रा की आत्महत्या के विरोध में शनिवार को कानपुर महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित पत्र सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मृतक छात्र के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी भी की। कानपुर महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष पवन गुप्ता के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने देशभर में लगातार सामने आ रहे परीक्षा घोटालों पर आक्रोश जताया। नेताओं ने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक जैसी घटनाओं ने छात्रों और अभिभावकों का भरोसा तोड़ दिया है तथा मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी के छात्र ऋतिक मिश्रा की आत्महत्या केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विफलता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि *अब नहीं देनी प्रतियोगी परीक्षा* जैसे शब्द छात्रों के टूटते विश्वास को दर्शाते हैं। कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है और उनकी आवाज को सड़क से सदन तक उठाने का काम करेगी। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि नीट पेपर लीक प्रकरण की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए तथा दिवंगत छात्र के परिवार को आर्थिक सहायता और न्याय दिया जाए। नेताओं ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष काउंसलिंग व्यवस्था लागू करने की भी मांग की। उनका कहना था कि यदि शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी तो युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित होता रहेगा।

नेशनल डेंगू डे पर रैली निकालकर स्वच्छता के प्रति किया जागरूक

जोधपुर (हिंस)। नेशनल डेंगू डे के अवसर पर सीएमएचओ डॉ. सुरेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आज शहर में व्यापक डेंगू जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत आमजन को डेंगू रोग से बचाव, साफ-सफाई एवं मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के प्रति जागरूक करने डेंगू जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेंद्र कच्छवाहा एवं आरसीएचओ डॉ. रूपेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, चिकित्सा कार्मिकों एवं एएनएमटीसी की छात्राओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में जागरूकता संदेशों से युक्त पोस्टर, बैनर एवं स्लोगन लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकालते हुए आमजन को डेंगू के प्रति जागरूक किया। रैली के दौरान लोगों को अपने घरों एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया।

राजस्थान बनेगा देश का अगला बड़ा इवेंट हब : हितेंद्र शर्मा

जयपुर (हिंस)। फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स (फोरम) की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आमेर रोड स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। समारोह में पूर्व अध्यक्ष मोहित माहेश्वरी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष हितेंद्र शर्मा को कार्यभार सौंपा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व मोहन भट्ट रहे। उनके साथ सुप्रसिद्ध संगीतकार सलिल भट्ट भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विश्व मोहन भट्ट ने कहा कि इवेंट इंडस्ट्री अब केवल आयोजनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह कला, संस्कृति, पर्यटन और लोगों को जोड़ने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। नई कार्यकारिणी में अजय चौहान और विनीत जैन ने उपाध्यक्ष, भुवनेश अग्रवाल ने महासचिव, कुलदीप सिंह ने कोषाध्यक्ष तथा सुनील विजयवर्गीय, यश माहेश्वरी, रोहित अजमेरा और अक्षत पुरोहित ने कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शपथ ली। समारोह में पूर्व अध्यक्ष महावीर प्रताप शर्मा, हरप्रीत बग्गा और इवेंट गुरु अरशद हुसैन सहित इवेंट, होटल, ट्रैवल और वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एवं *इवेंटस्थान* के आयोजन की भी घोषणा की गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हितेंद्र शर्मा ने कहा कि फोरम राजस्थान की इवेंट इंडस्ट्री को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में वेडिंग डेकोर, कैटरिंग, लोक कलाकारों और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन बड़े और लग्जरी आयोजनों में अभी भी दिल्ली और मुंबई की कंपनियों का दबदबा बना हुआ है।

पीएम की अपील पर एमजीएस विवि में विद्यार्थियों के लिए आनलाइन कक्षाओं के आयोजन का निर्णय

बीकानेर (हिंस)। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का अनुसरण करते हुए महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित ने निर्णय लेते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश प्रदान किये है। विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली संचालित होने के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में भी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे विद्यार्थियों की निर्धारित कालांश की पूर्ति होने पर परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सके। मीडिया प्रभारी उमेश शर्मा ने बताया कि कुलगुरु के इस निर्णय से विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय लाने एवं वापस घर छोड़ने के लिए उपयोग में आ रहे विश्वविद्यालय वाहन एवं विद्यार्थियों के स्वयं के वाहनों में ईधन की बचत की जा सकेगी।

पंजाब : बोरवेल में गिरे बच्चे को नौ घंटे बाद सुरक्षित निकाला

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब के होशियारपुर के गांव चक्क समाना में शुक्रवार शाम करीब चार बजे बोरवेल में गिरे चार वर्षीय बच्चे को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पंजाब पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के सहयोग से करीब नौ घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बोरवेल में गिरे बच्चे गुरकरन सिंह (पुत्र हरिंदर और आशा, मजदूर) को रात करीब 12-40 बजे बोरवेल से बाहर निकाला गया और तुरंत मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उपायुक्त आशिका जैन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मलिक ने रेस्क्यू अभियान का शुरुआत से नेतृत्व किया और पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए टीमों की दृढ़ता की भरपूर सराहना की। बचाव कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद उपायुक्त ने बताया

कि बच्चे को बचाने के बाद एंबुलेंस में चिकित्सकों की टीम के साथ आगे की जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि शाम करीब 4 बजे यह घटना हुई और सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि गुरकरन अपने घर के बगल में खुले बोरवेल में गिर गया था, जो कल खोदा जा रहा था। बोरवेल के बिल्कुल बगल में 30 फीट से अधिक गहरा गड्ढा खोदने के बाद बचाव टीमों ने बोर के साथ एक तंग रास्ता बनाकर शाफ्ट तक पहुंच कर काफी मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चा बोरवेल में गिरने के बाद करीब 30 फीट की गहराई पर फंस गया था। बचाव कार्य तेज करने के लिए जरूरी मशीनरी मौके पर लाई गई। जिला प्रशासन ने शाफ्ट में कैमरा और ऑक्सीजन पाइप भी नीचे उतारा, जिससे बच्चे की हरकतों को फुटेज के जरिए देखा जा रहा था। उपायुक्त ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम (40 से अधिक सदस्य) ने अपनी विशेषज्ञता से इस कठिन समय में ऑपरेशन को सुरक्षित ढंग से सफल बनाया। इस दौरान पंजाब के जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह और होशियारपुर से लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल, जो पूरे बचाव अभियान के दौरान मौके पर मौजूद रहे, ने गुरकरन को बचाने के लिए सभी टीमों द्वारा किए गए अथक प्रयासों की सराहना की। डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ, अन्य टीमों और स्थानीय गांव वासियों की मदद से बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने के लिए पुख्ता प्रबंध किए, जिनकी वजह से गुरकरन की जान बच सकी। सांसद डॉ. चब्बेवाल ने कहा कि यह बहुत नाजुक ऑपरेशन था और टीमों के लगातार प्रयासों से करीब सात घंटे की जद्दोजहद के बाद इसे सफल बनाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मलिक ने भी बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव टीमों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि टीमों का जज्बा बेहद सराहनीय था, जिसकी वजह से गुरकरन की जान बच गई।

भ्रष्टाचार के आरोप में महिला पीसीएस अधिकारी गिरफ्तार

चंडीगढ़ (हिंस)। जम्मू-कश्मीर-राजस्थान हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण मामले में करोड़ों की हेराफेरी के आरोप में पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर की एसडीएम अनुप्रीत कौर रंधावा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार सुबह उनके तरनतारन जिला स्थित आवास पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार अनुप्रीत कौर रंधावा के खिलाफ कुल 1 करोड़ 63 लाख रुपए के गबन का मामला चल रहा था। उस समय अनुप्रीत तरनतारन के पट्टी में तैनात थीं। इसी मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, राजस्थान-जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के निर्माण के वक्त सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण के दौरान तत्कालीन तरनतारन की एसडीएम डॉ. अनुप्रीत कौर ने उन लोगों को लाभ पहुंचाया, जिनके पास जमीन नहीं थी। पट्टी के पूर्व एसडीएम नवराज सिंह बराड़ ने तत्कालीन उपायुक्त को 5 सितंबर 2018 को इस गबन के संबंध में शिकायत दी थी। आरोप था कि 9 जनवरी 2018 से 11 फरवरी 2019 बीच जमीन अधिग्रहण के एवज में सरकार की ओर से जारी 1 करोड़ 63 लाख की राशि 5 अपात्र लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई।

सड़क नहीं होने को लेकर ऊर्जा मंत्री के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, 21 दिवसीय आमरण अनशन शुरू

भागलपुर (हिंस)। जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत कांटीधार नवटोलिया, डीमहा, गोपालपुर नवगछिया के ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। सड़क, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार को बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के आवास के पास 21 दिवसीय आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आंदोलन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2007 से लगातार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक हालात जस के तस बने हुए हैं। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र से मंत्री बनने के बावजूद गांवों की तस्वीर नहीं बदली और आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अनशन स्थल पर लगाए गए बड़े पोस्टर में गांव की बदहाली को बेहद मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि सड़क नहीं रहने के कारण गर्भवती महिलाओं को खेत और कीचड़ भरे रास्तों से अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर गंगा नदी पार कर पढ़ाई करने जाते हैं। वहीं बीमार और घायल लोगों को समय पर इलाज नहीं मिलने से कई लोगों की जान तक चली गई। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क नहीं होने की वजह से शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है और लोगों को रोज भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पोस्टर में *आजाद भारत का गुलाम गांव* लिखकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला गया है। आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आंदोलन स्थल पर लगातार नारेबाजी हो रही है और लोग सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक सड़क निर्माण, पेयजल और आवागमन की समुचित व्यवस्था शुरू नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा।

शनि जयंती पर जयपुर शनिमय : मंदिरों में उमड़ी आस्था

जयपुर (हिंस)। ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिवार को राजधानी जयपुर पूरी तरह भक्ति और आस्था में सराबोर नजर आई। शनि जयंती, शनैश्चरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत के अवसर पर शहरभर के शनि मंदिरों, धार्मिक स्थलों और वट वृक्षों के आसपास श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दिनभर तेलाभिषेक, विशेष पूजा-अर्चना, भजन संध्या, झांकियों, महाआरती और भंडारों का दौर चलता रहा। बापू नगर जनता स्टोर स्थित श्री सिद्ध पीठ शनिधाम नवग्रह मंदिर में महंत शंकर लाल महाराज के सानिध्य में भगवान शनिदेव का 151 किलो तेल से महातेलाभिषेक किया गया। भगवान को नवीन काली पोशाक धारण करवाई गई तथा फूल बंगला झांकी सजाकर लड्डुओं का भोग लगाया गया। मंदिर प्रवक्ता नारायण गौशिल ने बताया कि श्रद्धालुओं ने शनि दोष और साढ़ेसाती से मुक्ति की कामना करते हुए काले तिल, सरसों का तेल, काली दाल, काला छाता सहित विभिन्न काली वस्तुएं अर्पित कीं। महाआरती के बाद पंगत प्रसादी भंडारे का आयोजन हुआ। वहीं सिद्धार्थ नगर रेलवे हेड ऑफिस के पीछे स्थित श्री शनिदेव मंदिर में मंदिर पुजारी कमलेश शर्मा के सानिध्य में भगवान का 251 किलो तेल से तेलाभिषेक किया गया। इसके बाद फूलों से भव्य श्रृंगार कर नवीन पोशाक धारण करवाई गई तथा खीर, इमरती और शीतल व्यंजनों का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं ने 1008 दीपकों से भगवान

की महाआरती कर भक्तिमय वातावरण बनाया। मंदिर प्रवक्ता कमलेश शर्मा ने बताया कि सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं द्वारा तेलाभिषेक और दान-पुण्य का सिलसिला जारी रहा। शनिदेव जयंती पर अमृत ग्रुप की ओर से विशेष पूजा-अर्चना भी की गई। कार्यक्रम में समाजसेवी राजन सरदार, पंडित दीपक, कमलेश, प्रकाश शर्मा सहित गीता देवी, यशवंत सिंह, दीवीशा, जितेंद्र सिंह, वानी, जानवी, नंदिनी, ताक्षवी, मलिंगा, शनाया एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। एमआई रोड स्थित शनिधाम मंदिर में महंत मगन गौड़ के सानिध्य में पंचामृत एवं महातेला अभिषेक किया गया। शाम को फूल बंगला और रंगीन बर्फ से विशेष बर्फानी झांकी सजाई गई, जिसने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। शनिदेव को कचोरी, खीर और मालपुए का भोग लगाया गया। चारदीवारी के मोहल्ला डाकोतान स्थित शनि मंदिर, सिंधी कैंप, मानसरोवर, टोंक रोड, सीकर रोड, मुरलीपुरा, वैशाली नगर, जगतपुरा, खातीपुरा, मालवीय नगर, सिरसी रोड और दिल्ली रोड स्थित मंदिरों में भी दिनभर विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन हुए। इस बार शनि जयंती का विशेष महत्व रहा, क्योंकि 20 वर्षों में चौथा अवसर था जब शनि जयंती शनिवार को आई। भरणी नक्षत्र, शोभन और सौभाग्य योग के विशेष संयोग में श्रद्धालुओं ने शनि कृपा की कामना की। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने तिल, तेल, काला वस्त्र, उड़द और अन्य सामग्री का दान कर शनि दोष से मुक्ति की प्रार्थना की। शहर में वट सावित्री व्रत भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा और सोलह श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा-अर्चना की तथा पति की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने वट वृक्ष की सात परिक्रमा कर कच्चा सूत बांधा और सावित्री-सत्यवान कथा का श्रवण किया। कई स्थानों पर सामूहिक भजन-कीर्तन और कथा वाचन भी आयोजित हुए। पंडित राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सावित्री ने अपने तप और समर्पण से यमराज से पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हाथोज स्थित श्री दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर में शनैश्चरी अमावस्या पर विशेष धार्मिक आयोजन हुए। हाथोज धाम पीठाधीश्वर स्वामी बालमुकुंदाचार्य के सानिध्य में बालाजी महाराज का चमेली के तेल से अभिषेक किया गया तथा मोगरे के फूलों की आकर्षक झांकी सजाई गई। महंत पुरुषोत्तम दास महाराज ने बताया कि श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं को सिकंजी और कैरी की छाछ वितरित की गई। संध्याकालीन महाआरती और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए।

भारत में बेरोजगारी दर छह माह के उच्च स्तर पर : अप्रैल में 5.2 फीसदी तक पहुंची, शहरों में मामूली सुधार

नई दिल्ली

देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर 5.2 फीसदी हो गई। यह पिछले छह महीनों का उच्चतम स्तर है। मार्च में यह दर 5.1 फीसदी थी। इससे पहले अक्तूबर, 2025 में बेरोजगारी दर 5.2 फीसदी दर्ज की गई थी।

केंद्र सरकार के सर्वे में 3.74 लाख+ लोग शामिल – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर मार्च के 6.8 फीसदी से घटकर अप्रैल में 6.6 फीसदी रह गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 4.3 फीसदी से बढ़कर 4.6 फीसदी हो गई। देशभर में यह सर्वे 3,74,243 लोगों से जुटाई गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।

महिलाओं की बेरोजगारी – पुरुषों में बेरोजगारी अप्रैल में 5.1 फीसदी रही, जो मार्च में 5 फीसदी थी। ग्रामीण पुरुष बेरोजगारी दर 4.4 फीसदी से बढ़कर 4.7 फीसदी हो गई, जबकि शहरों में यह 6.1 फीसदी से घटकर 5.9 फीसदी पर आ गई। महिलाओं की बेरोजगारी मार्च के 5.3 फीसदी से बढ़कर 5.4 फीसदी हो गई।

डब्ल्यूपीआर यानी कार्यरत आबादी का अनुपात – ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी बढ़कर 4.4 फीसदी हो गई, जबकि शहरी महिला बेरोजगारी दर घटकर 8.5 फीसदी रही। यह पिछले वर्ष अप्रैल के बाद सबसे निचला स्तर है। वीमेन पार्टिसिपेशन रेशियो (डब्ल्यूपीआर) यानी कार्यरत आबादी का अनुपात अप्रैल में 52.2 फीसदी रहा, जो मार्च में 52.6 फीसदी था। शहरी क्षेत्रों में यह 46.8 फीसदी पर स्थिर रहा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में घटकर 54.9 फीसदी हो गया।

महिला श्रम बल भागीदारी में कमी – श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) अप्रैल में घटकर 55 फीसदी रही, जबकि मार्च में 55.4 फीसदी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 57.5 फीसदी एवं शहरी क्षेत्रों में 50.1 फीसदी दर्ज की गई। अप्रैल, 2026 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर कम होकर 33.9 फीसदी रही, जबकि मार्च में यह 34.4 फीसदी थी। ग्रामीण महिलाओं का एलएफपीआर 38.2 फीसदी और शहरी महिलाओं का 25 फीसदी दर्ज किया गया।

न्यूज ब्रीफ

नई सेल्टस को लेकर ग्राहकों के बीच चर्चा तेज

नई दिल्ली। किआ कंपनी की नई सेल्टास को लेकर ग्राहकों के बीच पहले से ही काफी उत्साह है। अब हाइब्रिड वर्जन की खबर ने इसकी चर्चा और बढ़ा दी है। हाल ही में इस एसयूवी का फुली कैमोफ्लाज्ड माडल टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इसका आधिकारिक खुलासा कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार नई सेल्टास हाइब्रिड में डिजाइन के स्तर पर ज्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे। स्पाई तस्वीरों में इसमें फेसलिफ्टेड माडल जैसी कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स दिखाई दी हैं। इसके अलावा फ्लश टाइप डोर हैंडल और नए अलाय व्हील्स भी देखने को मिले हैं। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी मुख्य बदलाव इंजन और मैकेनिकल सेटअप में करने जा रही है। माना जा रहा है कि कंपनी इसमें नया 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दे सकती है, जो एटकिंसन–साइकिल तकनीक पर आधारित होगा। इसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और छोटी बैटरी पैक भी जोड़ी जाएगी। यह हाइब्रिड सेटअप करीब 155 बीएचपी की ताकत और 265 एनएम टार्क जनरेट कर सकता है। यह पावर मौजूदा टर्बो पेट्रोल इंजन के लगभग बराबर मानी जा रही है। कंपनी नई सेल्टास के साथ दो नए टाप–एंड ट्रिम भी लाने की तैयारी में है। इनमें जीटीएक्स प्लस और एक्स–लाइन (ओ) शामिल होंगे। इन वेरिएंट्स में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और बेहतर टेक्नोलाजी मिलने की उम्मीद है। बेहतर माइलेज, दमदार परफार्मेंस और आधुनिक फीचर्स के चलते यह एसयूवी लान्च के बाद मिड–साइज एसयूवी सेगमेंट में बड़ा मुकाबला पैदा कर सकती है। किआ इंडिया अपनी एसयूवी लाइनअप को लगातार मजबूत कर रही है और सेल्टास का हाइब्रिड वर्जन इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

टाटा सिएरा ईवी को जल्द लान्च करने की तैयारी

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा सिएरा को जल्द लान्च करने की तैयारी कर रही है। ग्राहकों के बीच इसे लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक यह एसयूवी जून 2026 के आखिर तक बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है। नई सिएरा ईवी को कंपनी अपने एक्टिव.ईवी+ स्केटबोर्ड प्लेटफार्म पर तैयार कर रही है। यह माड्यूलर प्लेटफार्म इलेक्ट्रिक और इंटरनल कंबशन इंजन दोनों तकनीकों को सपोर्ट करता है। डिजाइन की बात करें तो इसमें बंद फ्रंट ग्रिल, स्प्लिट हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, फ्लश डोर हैंडल और कनेक्टेड एलईडी लाइट बार जैसे आधुनिक फीचर्स देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इसे 55 केडब्ल्यूएच और 65 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश कर सकती है। बड़ी बैटरी वाला माडल एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम होगा। इसके अलावा सभी वेरिएंट में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इंटीरियर में सिएरा ईवी को बेहद प्रीमियम बनाया गया है। इसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर के लिए अलग डिस्प्ले दिया जा सकता है।

टाटा ट्रस्ट्स की बैठक स्थगितः एमएससीसी ने कहा- शिकायत में गंभीर मुद्दे; कंपनी बोली- चैरिटी आयुक्त का आदेश एकतरफा

मुंबई। महाराष्ट्र राज्य चैरिटी आयुक्त ने टाटा ट्रस्ट्स को 16 मई को होने वाली बोर्ड आफ ट्रस्टीज की महत्वपूर्ण बैठक स्थगित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड संरचना से संबंधित कथित नियमों के उल्लंघन की लंबित जांच के कारण दिया गया है। टाटा ट्रस्ट्स ने इस निर्देश को एकतरफा बताया है। पहले 8 मई को होनी थी बैठक, अब एमएससीसीने जांच के आदेश दिए चैरिटी आयुक्त ने ट्रस्ट को जांच पूरी होने तक ऐसी कोई भी बैठक न करने को कहा है। टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस का 66 फीसदी हिस्सा है। यह बैठक टाटा संस की लिस्टिंग और अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण थी। 8 मई को होनी थी, जिसे 16 मई के लिए स्थगित किया गया था। टाटा ट्रस्ट्स ने कहा कि यह निर्देश केवल सर रतन टाटा ट्रस्ट से संबंधित है और बिना किसी सूचना या सुनवाई के जारी किया गया था। महाराष्ट्र राज्य, मुंबई के चैरिटी आयुक्त अमोघ एस कालोटी ने जांच का आदेश दिया है। नियमों के उल्लंघन की शिकायत चैरिटी आयुक्त ने महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स अधिनियम की धारा 36ए(1) के तहत निर्देश जारी किया है।

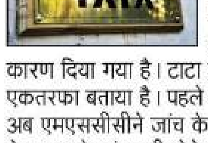

अधिक मास में साबूदाना–फरियाली उत्पादों की मांग डेढ़ गुना तक बढ़ने के है आसार

आवक घटने से कीमतों में उछाल संभव, साबु ट्रेड ने की निर्बाध आपूर्ति की पुख्ता तैयारी

सेलम/इंदौर

आगामी 17 मई से प्रारंभ हो रहे पवित्र पुरुषोत्तम मास (अधिक मास) के दौरान व्रत–उपवास की फलाहारी वस्तुओं की मांग में भारी उछाल आने का अनुमान है। साबु ट्रेड के अनुसार, इस वर्ष साबूदाना, मोरधन, मखाना और फरियाली आटे जैसी वस्तुओं की खपत पिछले वर्षों के मुकाबले करीब डेढ़ गुना तक बढ़ सकती है। हालांकि, कच्चे माल की कमी के चलते इनके दामों में तेजी देखी जा सकती है, लेकिन बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने विशेष कार्ययोजना तैयार की है।

साबु ट्रेड के संस्थापक चेयरमैन गोपाल साबु ने बताया कि वर्तमान में कसावा कंद का सीजन समापन की ओर है, जिसके कारण साबूदाने की आवक काफी कमजोर पड़ गई है। मांग और आपूर्ति के इस अंतर को देखते हुए उन्होंने देश भर के वितरकों और स्टाकिस्टों से पर्याप्त स्टाक बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अधिक मास उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत आस्था का समय है, अत: हमारा दायित्व है कि उन्हें शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद आसानी से मिलते रहें। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद कंपनी निर्बाध आपूर्ति शृंखला बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा करते हुए गोपाल साबु ने कहा कि रूस–यूक्रेन युद्ध, मध्य–पूर्व में तनाव और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के कारण खाद्य पदार्थों की उत्पादन लागत बढ़ी है। चीन के प्रापर्टी संकट और बदलती व्यापार नीतियों ने भी वैश्विक विकास की रफ्तार धीमी की है, जिसका आंशिक प्रभाव भारतीय बाजारों पर भी संभव है। इसके बावजूद साबु ट्रेड अपने चार दशकों के अनुभव और विश्वसनीयता के साथ गुणवत्ता से समझौता किए बिना निरंतर आपूर्ति के लिए संकल्पित है।

तमिलनाडु के सेलम से संचालित साबु ट्रेड पिछले 40 वर्षों से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक रहा है। कंपनी के विभिन्न ब्रांड्स ने देशभर के उपभोक्ताओं के बीच गहरा विश्वास अर्जित किया है। इसमें सच्चासाबु ब्रांड के अंतर्गत एगमार्क साबूदाना, पापड़ और न्यूट्रीदाना जैसे उत्पाद आते हैं, जबकि अल्पाहार ब्रांड एगमार्क हल्दी, नारियल बुरादा, मखाना और मोरधन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही, कुकरीजाकी ब्रांड के माध्यम से कंपनी पौष्टिक मिलेट्स और पारंपरिक खिचीया पापड़ की विस्तृत श्रृंखला पेश करती है। इन सभी उत्पादों की शुद्धता और स्वाद ने इन्हें भारतीय परिवारों का प्रिय बनाया है।

सेडान होंडा सिटी का फेसलिफ्ट माडल होगा 22 को पेश

नई दिल्ली। होंडा की अपने लोकप्रिय सेडान होंडा सिटी का फेसलिफ्ट माडल 22 मई को लान्च करने की तैयारी है। इस औपचारिक लान्च से पहले ही कार की तस्वीरें आनलाइन लीक हो गई हैं। तस्वीरों में होंडा सिटी का नया और ताजा फ्रंट डिजाइन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें शार्प एलईडी हेडलाइट्स, एक पुन: डिजाइन की गई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए आकर्षक अलाय व्हील्स शामिल हैं, जो कार को एक अधिक आधुनिक और स्पोर्टी लुक प्रदान करते हैं। यह बदलाव सिटी को अपने प्रतिस्पर्धियों के सामने और भी आकर्षक बना देगा। कार के इंटीरियर में भी बड़े बदलावों की उम्मीद है, रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें एक बड़ी फ्री–स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, आरामदायक वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट और एक 360 डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं। ये फीचर्स न केवल ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाएंगे बल्कि यात्रियों के लिए भी सुविधा और लक्जरी प्रदान करेंगे। इंजन के मोर्चे पर, कंपनी कार में मौजूदा विश्वसनीय 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड इंजन विकल्प को बरकरार रख सकती है। यह इंजन 121 हार्सपावर तक की ताकत उत्पन्न करता है, जो बेहतरीन प्रदर्शन और ईंधन दक्षता का संतुलन प्रदान करता है। फेसलिफ्ट माडल की कीमत मौजूदा संस्करण से थोड़ी अधिक होने की संभावना है, जो नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट को ध्यान में रखते हुए उचित लगती है।

कई नई बाइक लान्च करने की योजना बना रही रायल एनफील्ड

नई दिल्ली

बाइक निर्माता रायल एनफील्ड कंपनी 650 सीसी और 750 सीसी प्लेटफार्म पर कई नई मोटरसाइकिलें लान्च करने की योजना बना रही है। रायल एनफील्ड अब इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। कंपनी सबसे पहले नए 750 सीसी प्लेटफार्म पर आधारित हिमालयन 750 लान्च कर सकती है।

इसके अलावा बड़ी कान्टिनेंटल जीटी पर भी काम चल रहा है। हालांकि मौजूदा 650 सीसी कान्टिनेंटल जीटी की बिक्री जारी रहेगी। नया प्लेटफार्म कंपनी की सबसे प्रीमियम और पावरफुल मोटरसाइकिल लाइनअप माना जा रहा है। वहीं क्लासिक लुक पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए बुलेट 650 भी जल्द बाजार में दस्तक दे सकती है। इसमें 648 सीसी इंजन मिलेगा, जो लगभग 47 बीएचपी की ताकत देगा। बाइक में 6–स्पीड गियरबाक्स और स्लिपर क्लच जैसे आधुनिक फीचर्स भी होंगे। एडवेंचर बाइक पसंद करने वालों के लिए, कंपनी हिमालयन 440 भी लाने की तैयारी कर रही है। इसे अपेक्षाकृत किफायती कीमत पर पेश किया जा सकता है, ताकि ज्यादा ग्राहक एडवेंचर बाइकिंग का अनुभव ले सकें। रायल एनफील्ड इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी बड़ा दांव खेलने जा रही है। कंपनी फ्लाइंग फ्ली सी6 के बाद अब नई इलेक्ट्रिक स्क्रैम्बलर बाइक एस6 लाने की तैयारी में है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक हिमालयन पर भी तेजी से काम चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 और 2027 रायल एनफील्ड के लिए बेहद अहम साल साबित हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी हर तरह के ग्राहकों के लिए नए माडल और तकनीक पेश करने जा रही है।

पेट्रोल के निर्यात पर 3 प्रति लीटर टैक्स लगा

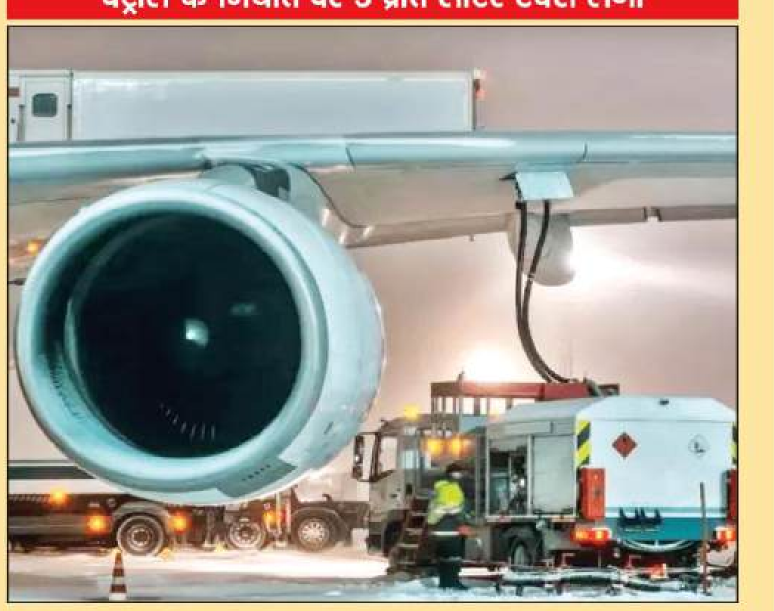

नई दिल्ली। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर 3 प्रति लीटर का विंडफाल टैक्स लगा दिया है। डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स घटाया है। अमेरिका–इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 डालर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। भारत में तेल की कमी न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है।

टीवीएस रेडर, स्प्लेंडर और पल्सर को दे रही कड़ी टक्कर

नई दिल्ली

भारतीय दोपहिया बाजार में टीवीएस मोटर की लोकप्रिय मोटरसाइकिल टीवीएस रेडर 125 ने एक बड़ी और प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है। अब तक इस स्पोर्टी बाइक की कुल बिक्री 19 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है। मार्च 2026 तक, इसकी घरेलू और निर्यात बिक्री को मिलाकर कुल 19,07,277 यूनिट्स दर्ज की गई हैं। टीवीएस रेडर को सितंबर 2021 में लान्च किया गया था, और इतने कम समय में यह 125 सीसी सेगमेंट की सबसे तेजी से बढ़ने वाली और सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकिलों में से एक बन गई है।

टीवीएस रेडर में 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 11.2 बीएचपी की ताकत और 11.2 न्यूटन मीटर का टार्क उत्पन्न करता है, जो शहरी और इंटरसिटी यात्रा के लिए पर्याप्त शक्ति और दक्षता प्रदान करता है। बाइक में एलईडी हेडलाइट, पूरी तरह से डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और दो राइड मोड जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जो इसे युवाओं के बीच खास पसंद बनाते हैं। कंपनी का कहना है कि इसका आकर्षक और स्पोर्टी डिजाइन, साथ ही अत्याधुनिक तकनीक, विशेष रूप से युवा ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रही है। वित्त वर्ष 2024 में, टीवीएस रेडर टीवीएस मोटर की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बन गई थी, जो इसकी बाजार में मजबूत पकड़ का प्रमाण है। भारतीय बाजार में, टीवीएस रेडर का सीधा मुकाबला हीरो स्प्लेंडर, बजाज पल्सर और होंडा शाइन जैसी इस सेगमेंट की अन्य लोकप्रिय बाइकों से होता है।

एयू स्माल फाइनेंस बैंक ने मनाया मातृ शक्ति का उत्सव; देशभर में हुई 500 से अधिक गतिविधियाँ

30 शहरों के 40 हजार से ज्यादा प्रतिभागियों ने दर्ज कराई उपस्थिति, स्थानीय स्तर पर बढ़ाया सामुदायिक जुड़ाव

मुंबई

भारत के सबसे बड़े स्माल फाइनेंस बैंक, एयू स्माल फाइनेंस बैंक ने मदर्स डे के अवसर पर देशव्यापी सामुदायिक जुड़ाव की एक विशाल पहल की। बैंक ने 8 से 14 मई के बीच हाइपरलोकल गतिविधियों के माध्यम से माताओं और महिलाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।

इस सात दिवसीय अभियान में देशभर के करीब 40,000 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जिनमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रही। उल्लेखनीय है कि एयू एसएफबी को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।

मदर्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और माताओं को उनके ही परिवेश में सम्मानित करना था। इसके लिए आवासीय कालोनियों, आरडब्ल्यूए, कार्पोरेट पार्कों और स्थानीय केंद्रों में 500 से अधिक शाखाओं के माध्यम से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली–एनसीआर, जयपुर, इंदौर, भोपाल, मुंबई और अहमदाबाद सहित देश के 30 प्रमुख शहरों में स्थानीय स्तर पर सार्थक वार्तालाप और साझा अनुभवों के माध्यम से सामुदायिक संबंधों को और गहरा किया गया।

कार्ड ग्राहकों के लिए विशेष आफर्स की सौगात

जमीनी स्तर पर आयोजित गतिविधियों के साथ ही बैंक ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए भी विशेष मदर्स डे अभियान चलाया। इसके तहत बैंक ने 10 प्रसिद्ध ब्रांड्स के साथ साझेदारी कर ज्वेलरी, वेलनेस, ट्रैवल, हेल्थकेयर और टेक्नोलाजी जैसी श्रेणियों में आकर्षक छूट और आफर्स प्रदान किए। इससे ग्राहकों को अपने जीवन की विशेष महिलाओं के लिए उत्सव को और भी यादगार बनाने का अवसर मिला।

विश्वास और सहभागिता पर केंद्रित पहल

एयू स्माल फाइनेंस बैंक की यह पहल डिजिटल प्लेटफार्म से आगे बढ़कर पारंपरिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूती देने के प्रयासों का हिस्सा है। बैंक का लक्ष्य केवल बैंकिंग सेवाएं देना ही नहीं, बल्कि विश्वास और भागीदारी पर आधारित एक सुदृढ़ ग्राहक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक और भावनात्मक जुड़ाव बनाने में बैंक को बड़ी सफलता मिली है।

आईपीएल 2026 : पंत ने बताया क्यों नहीं उतरे बल्लेबाजी करने, बोले–ज्यादा सोच टीम को नुकसान पहुंचा सकती है

लखनऊ

लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के कप्तान ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में उस समय बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे, जब टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए लगातार तीन विकेट गंवा दिए थे। मैच के बाद पंत ने खुलासा किया कि यह फैसला उन खिलाड़ियों को मौका देने के लिए लिया गया, जिन्हें आईपीएल 2026 में ज्यादा बल्लेबाजी का अवसर नहीं मिला था। 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एलएसजी ने 12वें ओवर तक बिना विकेट खोए 135 रन बना लिए थे। इसके बाद टीम ने नौ रन के भीतर तीन विकेट गंवा दिए। इसके बावजूद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए नहीं आए। निकोलस पूरन के बाद अब्दुल समद और मुकुल चौधरी को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। आखिरकार एलएसजी ने सात विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

मैच के बाद पंत ने कहा, मैं बल्लेबाजी के लिए तैयार था, लेकिन टीम मैनेजमेंट की ओर से विचार आया कि क्यों न उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाए जिन्हें इस सीजन में ज्यादा अवसर नहीं मिले हैं। मैं लगातार सोच रहा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं मैदान पर उतरना चाहता था। लेकिन कभी-कभी आपको टीम के सोच और फैसले का सम्मान करना पड़ता है। इस सीजन में पंत ने नंबर-4 से नीचे बल्लेबाजी नहीं की है। उन्होंने 11 पारियों में सात बार नंबर-3, तीन बार नंबर-4 और एक बार ओपनिंग की है। मैच के दौरान भी वह पैड पहनकर डगआउट में बैठे नजर आए थे। एलएसजी ने इस सीजन में कई बार अपनी ओपनिंग जोड़ी बदली। फिलहाल मिशेल मार्श और जोश इंग्लिस टीम के नियमित ओपनर हैं। एडेन मार्करम ने भी टीम के लिए ओपनिंग की है। टीम ने विदेशी खिलाड़ियों को शीर्ष क्रम में उतारने की रणनीति अपनाई थी, लेकिन यह लगातार सफल नहीं हो सकी। इंग्लिस लंबे समय तक टीम से बाहर रहे, जबकि मार्करम और निकोलस पूरन भी उम्मीद के मुताबिक रन नहीं बना सके।

रणनीति पर बात करते हुए पंत ने कहा, हमारा पहला विचार यही था कि दो विदेशी बल्लेबाज ओपनिंग करें और निकी (निकोलस पूरन) नंबर-3 पर बल्लेबाजी करें। लेकिन कई बार सोच को मैदान पर सही तरीके से लागू करना मुश्किल हो जाता है। हमें अपनी टीम पर भरोसा है, लेकिन निराशा तब होती है जब आपको पता हो कि आपकी टीम में क्षमता है, फिर भी छोटी-छोटी रणनीतिक बातों के कारण आप अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पाते।

न्यूज़ ब्रीफ

सैमसन हो सकते हैं भारतीय टी20 टीम के अगले कप्तान : रवि शास्त्री

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री का मानना है कि भारतीय टी20 टीम के अलग कप्तान संजू सैमसन होंगे। शास्त्री के अनुसार अगले दो से तीन साल में आप सैमसन को भारतीय टी20 टीम की कप्तानी करते देखेंगे। शास्त्री का मानना है कि सैमसन ने पिछले कुछ समय में कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर अपने को नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार कर लिया है और वह भविष्य में टीम इंडिया के लिए कप्तानी के बड़े दावेदार के तौर पर उभरेंगे। अभी भारतीय टीम की कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास है पर उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। ऐसे में चयनसमिति को भविष्य के लिए नये कप्तान की जरुरत है। सूर्यकुमार की कप्तानी में भारतीय टीम ने इसी साल टी20 विश्वकप जीत है पर उनका स्वयं का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। विश्वकप के बाद सूर्या आईपीएल में भी रन बनाने में असफल रहे। जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि चयनकर्ता उनसे आगे बढ़ने और 2028 टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिए एक नए और दीर्घकालिक कप्तान को पर्याप्त समय देने पर विचार कर रहे हैं। भारतीय टीम को आईपीएल के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड का भी दौरा करना है। इन दौरों के लिए भारतीय टीम की घोषणा के बाद चयनकर्ता नए कप्तान का नाम भी ले सकते हैं। इस दौड़ में अभी श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन दो नाम प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं पर श्रेयस अय्यर ने साल 2023 से कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है जबकि सैमसन ने हाल ही में संपन्न हुए टी20 विश्व कप में प्लेयर आफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था।

सुपर चेस क्लासिक रोमानिया 2026: प्रज्ञानानंद ने विश्व चैम्पियनशिप चैलेंजर सिंदारोव को हराया

बुखारेस्ट। भारत के ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने ग्रैंड चेस टूर के सुपर चेस क्लासिक रोमानिया 2026 के दूसरे दौर में शुक्रवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व चैम्पियनशिप चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव को काले मोहरों से मात दी। डिफेंडिंग चैंपियन प्रज्ञानानंद ने पहले दौर में फ्रांस के अलीरेज़ा फिरोज़ा के खिलाफ मुश्किल स्थिति से ड्रा बचाया था। दूसरे दौर में जीत दर्ज करने के बाद वह 2 मुकाबलों में 1.5 अंक के साथ शुरुआती बढ़त हासिल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि पहले दौर की सभी पांच बाजियां ड्रा रही थीं। यह जीत प्रज्ञानानंद के लिए बदले जैसी भी रही, क्योंकि 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में सिंदारोव ने उन्हें दोनों मुकाबलों में हराया था। उन मुकाबलों में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी सिंदारोव ने घोड़े की कुर्बानी देकर आक्रामक खेल दिखाया था। हालांकि इस बार भी सिंदारोव ने घोड़े की बलि दी, लेकिन प्रज्ञानानंद ने शांत और सटीक बचाव करते हुए अतिरिक्त मोहरे का फायदा उठाया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। सुपर चेस क्लासिक रोमानिया 2026, 10 खिलाड़ियों के बीच खेला जा रहा क्लासिकल राउंड-राबिन टूर्नामेंट है और यह 2026 ग्रैंड चेस टूर का दूसरा टूर्नामेंट है।

इस बार कई नये नियमों के साथ खेला जाएगा फीफा विश्वकप, बहस के दौरान मुंह नहीं छिपा सकेंगे खिलाड़ी

कोलकाता। 11 जून से अमेरिका कनाडा और मैक्सिको में होने वाले फीफा विश्वकम में इस बार फुटबाल में नए

नियम अपनाये जाएंगे। इसके तहत अब खिलाड़ी एक दूसरे से बहस के दौरान मुंह नहीं ढक सकेंगे। वहीं ऐसा करने पर उन्हें लाल कार्ड दिखाया जाएगा। यह कदम खिलाड़ियों के बीच मौखिक दुर्व्यवहार, विशेषकर नस्लीय टिप्पणियों को रोकने के लिए उठाया गया है। गौरतलब है कि चैम्पियंस लीग के दौरान रियाल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर के मैच के दौरान बेनफिका के जियानलुका प्रेस्टियानी के खिलाफ मुंह ढककर टिप्पणी की थी। जिसपर काफी विवाद हुआ था। इस मामले के सामने आने के बाद फीफा के सामने एक प्रस्ताव आया था। जिसमें इसपर रोक लगाने को कहा था। मौखिक दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाने के इस कदम के अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय फुटबाल के नियम तय करने वाली संस्था (आईएफएबी) ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसके तहत अब रेफरी के फैसले के विरोध में मैदान छोड़ने वाले किसी भी खिलाड़ी को लाल कार्ड दिखाया जा सकता है।

सीपीएल 2026 : त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने पोलार्ड, पूरन व नारायण को बरकरार रखा, आंद्रे रसेल अब जमैका किंग्समेन के लिए खेलेंगे

नई दिल्ली

कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2026 के लिए टीमों ने अपने स्क्वाड को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। डिफेंडिंग चैंपियन त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने अपने मजबूत वेस्टइंडियन कोर को बरकरार रखते हुए कीरोन पोलार्ड, निकोलस पूरन, सुनील नारायण और अकील होसैन को फिर से टीम में शामिल किया है। पिछले सीजन के फाइनल में प्लेयर आफ द मैच रहे अकील होसैन भी टीम के साथ बने रहेंगे।

वहीं, स्टार आलराउंडर आंद्रे रसेल अब सीपीएल 2026 में नई फ्रेंचाइजी जमैका किंग्समेन की ओर से खेलते नजर आएंगे। उनके साथ रोवमैन पावेल भी टीम में शामिल हुए हैं। पावेल टीम की कप्तानी संभालेंगे। इससे पहले उन्होंने 2022 में जमैका तलावाह्स को खिताब दिलाया था। जमैका किंग्समेन ने 19 वर्षीय बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर वितेल लाज़ को भी टीम में शामिल किया है। अंडर-19 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले लाज़ ने पांच मैचों में 10 विकेट हासिल किए थे और वेस्टइंडीज के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे।

गुयाना अमेजन वारियर्स के प्रमुख स्पिनर गुडाकेश मोती अब बारबाडोस ट्राइडेंट्स की ओर से खेलेंगे। मोती ने पिछले सीजन में इमरान ताहिर के साथ शानदार साझेदारी निभाई थी और टीम को सीपीएल तथा ग्लोबल सुपर लीग का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। बारबाडोस ने वेस्टइंडीज के ओपनर ब्रैंडन किंग को भी रिटेन किया है। गुयाना अमेजन वारियर्स ने मोती की जगह खैरी पियरे को शामिल किया है। टीम ने शिमरान हेटमायर, शाई होप, रोमारियो शेफर्ड और शमार जोसेफ को भी बरकरार रखा है। इसके अलावा क्वेंटिन सैम्पसन भी टीम में बने रहेंगे।

सेंट लूसिया किंग्स ने रोस्टन चेज और मैथ्यू फोर्डे को वापस टीम में शामिल किया है। वहीं, कैरेबियन के उभरते बल्लेबाज ज्वेल एंड्रयू एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स से सेंट लूसिया किंग्स में शामिल हुए हैं।

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने काइल मेयर्स, आंद्रे फ्लेचर और एलिक अथानाज़े को रिटेन किया है। जेसन होल्डर भी टीम के साथ बने रहेंगे। इसके अलावा टीम ने सीपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज जानसन चार्ल्स को भी शामिल किया है। इविन लुईस अब फाल्कन्स के लिए खेलेंगे।

सीपीएल 2026 का आयोजन इस बार रिकार्ड आठ देशों में किया जाएगा। टूर्नामेंट 7 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा और इसकी टक्कर द हंड्रेड टूर्नामेंट से भी होगी।

सीपीएल 2026: सभी टीमों के स्क्वाड

एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स

अल्जारी जोसेफ, इविन लुईस, फैबियन एलन, जेडन सील्स, आमिर जंगू, शमार स्प्रिंगर, जहमार हैमिल्टन, रहकीम कार्नवाल, एंडरसन फिलिप, करीमा गोर, एंडरसन महासे, जोशुआ जेम्स।

बारबाडोस ट्राइडेंट्स

गुडाकेश मोती, शेरफेन रदरफोर्ड, ब्रैंडन किंग, जैकरी कार्टर, कदीम एलेन, रेमन सिमंड्स, शैड्रैक डेसकार्टे, जिशान मोटारा, जाकीम पोलार्ड, जोहान लेन, कोफी जेम्स।

गुयाना अमेजन वारियर्स

शिमरान हेटमायर, रोमारियो शेफर्ड, शाई होप, खैरी पियरे, शमार जोसेफ, रोनाल्डो अलीमोहम्मद, वीरासामी पर्माल, मैथ्यू नंदू, जोनाथन बैन लैंगे, मवेंद्र डिंडयाल, इसाई थार्न, क्वेंटिन सैम्पसन।

जमैका किंग्समेन

रोवमैन पावेल, आंद्रे रसेल, कीमो पाल, कोसी कार्टी, जेडियाह ब्लेड्स, शाककेरे पैरिस, ओडियन स्मिथ, वितेल लाज़, रोमैने मारिस, किर्क मैकेंज़ी, केल्विन पिटमैन, जीवर रायल।

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स

जानसन चार्ल्स, जेसन होल्डर, काइल मेयर्स, आंद्रे फ्लेचर, केविन विकहम, ओबेड मैकाय, अशमीड नेड, जेरमिया लुईस, एलिक अथानाज़े, मिकाह मैकेंज़ी, नवीन बिदाइसी, मिकाइल लुईस।

सेंट लूसिया किंग्स

रोस्टन चेज, ज्वेल एंड्रयू, मैथ्यू फोर्डे, कामिल पूरन, डैरन नेड, मैककेनी क्लार्क, जोशुआ बिशप, डेमियन जोआकिम, कीआन गैस्टन, अमारी गुडरिज, जोहान जेरमिया, अकीम आगस्टे।

त्रिनबागो नाइट राइडर्स

सुनील नारायण, निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड, अकील होसैन, जस्टिन ग्रीव्स, डोमिनिक ड्रेक्स, जाइड गूली, डेक्सटर स्वीन, टेरेंस हिंड्स, नाथन एडवर्ड, जोशुआ डा सिल्वा, अब्दुल रहीम टापिन।

विराट कोहली का दर्द छलका, बोले हर बार खुद को साबित क्यों करूं

नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर अपने भावुक बयान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक पाडकास्ट बातचीत के दौरान उन्होंने अपने करियर, टेस्ट क्रिकेट से विदाई और टीम में अपनी भूमिका को लेकर खुलकर बात की। कोहली के शब्दों में भावनाएं भी थीं और नाराजगी भी। उनके बयान ने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है कि क्या भारतीय क्रिकेट अपने सबसे बड़े खिलाड़ियों को सही सम्मान और स्पष्टता दे पा रहा है। कोहली ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी अपना घर, परिवार और निजी जिंदगी छोड़कर पूरी तरह क्रिकेट को समर्पित कर देता है, तो वह सिर्फ इतना चाहता है कि उस पर भरोसा किया जाए। उन्होंने इशारों में कहा कि बार-बार खुद को साबित करने की स्थिति किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल होती है। उनके बयान को टेस्ट क्रिकेट से उनके अचानक संन्यास से जोड़कर देखा जा रहा है। क्रिकेट फैंस लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा क्यों कहा और क्या इसके पीछे चयनकर्ताओं या टीम प्रबंधन का दबाव था। पाडकास्ट में कोहली काफी भावुक नजर आए। आमतौर पर मैदान पर आक्रामक अंदाज में दिखने वाले विराट इस बार अंदर से आहत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी खिलाड़ी को हर बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़े, तो वह स्थिति मानसिक रूप से बेहद थका देने वाली हो जाती है। उनके बयान से यह साफ महसूस हुआ कि वह अपने भविष्य को लेकर स्पष्टता चाहते हैं और अनिश्चितता में नहीं रहना चाहते। सूत्रों के मुताबिक, टेस्ट क्रिकेट में उनकी भूमिका और प्रदर्शन को लेकर टीम प्रबंधन तथा चयन समिति के भीतर सवाल उठे थे। माना जा रहा है कि इसी कारण उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से दूरी बनाने का फैसला लिया। हालांकि कोहली ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों में निराशा साफ दिखाई दी। इसके बावजूद विराट ने अपने करियर और मिले अवसरों के लिए भगवान का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए खेलना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि कोहली अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं और उनके अंदर वही जुनून और आग बाकी है, जिसने उन्हें दुनिया के महान बल्लेबाजों में शामिल किया।

आईसीसी ने क्रिकेट कनाडा की फंडिंग रोकी

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने क्रिकेट कनाडा के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उसकी फंडिंग पर रोक लगा दी है। यह फैसला बोर्ड में लंबे समय से चल रहे गवर्नेंस और प्रशासनिक विवादों के कारण लिया गया है। आईसीसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही क्रिकेट कनाडा को संकेत दे दिए थे कि यदि शासन संबंधी मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो अगले छह महीनों तक मिलने वाली वित्तीय सहायता रोक दी जाएगी। अब परिषद ने बिना देरी किए इस फैसले को लागू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फंडिंग रोके जाने के बावजूद क्रिकेट गतिविधियों और हाई परफार्मेंस कार्यक्रमों पर तत्काल असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह क्रिकेट कनाडा के लिए बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है। कनाडाई क्रिकेट बोर्ड एक एसोसिएट सदस्य के तौर पर आईसीसी से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर काफी हद तक निर्भर है। वर्ष 2024 के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार बोर्ड की कुल आय का लगभग 63 प्रतिशत हिस्सा आईसीसी से प्राप्त होता था। क्रिकेट कनाडा को कुल 5.7 मिलियन कनाडाई डालर की आय में से करीब 3.6 मिलियन कनाडाई डालर आईसीसी से मिलते थे, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 25 करोड़ रुपये के बराबर है।

आईपीएल 2026 : आरसीबी व चेन्नई ने चोटिल खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान

नई दिल्ली

आईपीएल 2026 का लीग चरण अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है और प्लेआफ की जंग लगातार रोमांचक होती जा रही है। जैसे-जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, टीमों के लिए हर जीत बेहद अहम बनती जा रही है। इस बीच रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने पिछले मुकाबले में सीजन की आठवीं जीत दर्ज कर प्लेआफ में जगह लगभग पक्की कर ली है। टीम फिलहाल अंकतालिका में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स छह जीत के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है और प्लेआफ की दौड़ में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। अपने आगामी मुकाबलों से पहले दोनों टीमों ने चोटिल खिलाड़ियों के स्थान पर नए खिलाड़ियों को शामिल करने का फैसला किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने तेज गेंदबाज खलील अहमद की जगह घरेलू क्रिकेटर और मीडियम पेसर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है। वहीं रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने श्रीलंकाई तेज गेंदबाज नुवान तुषारा की जगह इंग्लैंड के अनुभवी पेसर रिचर्ड ग्लीसन को साइन किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक खलील अहमद और नुवान तुषारा दोनों चोट के कारण मौजूदा सीजन से बाहर हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने कुलदीप यादव को 30 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा है। कुलदीप इससे पहले साल 2021 में राजस्थान रायल्स के लिए आईपीएल में पदार्पण कर चुके हैं। हालांकि अब तक उन्हें आईपीएल में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं और उन्होंने कुल तीन मैच ही खेले हैं। चेन्नई प्रबंधन को उम्मीद है कि वह टीम के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देंगे। दूसरी तरफ रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रिचर्ड ग्लीसन को 1.6 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया है। 38 वर्षीय ग्लीसन इंग्लैंड के लिए छह टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं और नौ विकेट अपने नाम कर चुके हैं। ग्लीसन को टी20 क्रिकेट का काफी अनुभव हासिल है और वह डेथ ओवरों में अपनी सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। रिचर्ड ग्लीसन इससे पहले आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स और 2025 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें भारतीय परिस्थितियों का अच्छा अनुभव है। आईपीएल 2026 के निर्णायक दौर में दोनों टीमों को अपने नए खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी, क्योंकि प्लेआफ की दौड़ अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है।

आस्ट्रेलिया दौरे से पहले दबाव झेलने के लिए पूरी तरह तैयार भारतीय महिला हाकी टीम : सलीमा टेटे

नई दिल्ली

भारतीय महिला हाकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आस्ट्रेलिया दौरे से पहले कहा है कि टीम किसी भी तरह के दबाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) केंद्र में टीम का प्रशिक्षण शिविर बेहद मेहनत और अनुशासन के साथ चल रहा है।

अर्जेंटीना दौरे में मिले अनुभव को सकारात्मक बताते हुए सलीमा ने कहा कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले आगामी विश्व कप और एशियाई खेलों जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होंगे।

सलीमा टेटे ने हाकी इंडिया के हवाले से कहा, आस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है और उनके खिलाफ खेलने से हमें उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिलेगा। हम इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। कोचिंग स्टाफ लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहा है।

उन्होंने युवा खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि टीम में नई प्रतिभाओं को लगातार अवसर दिए जा रहे हैं और वे अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं। कप्तान के अनुसार टीम का संतुलन और भविष्य दोनों मजबूत दिखाई दे रहे हैं।

फिटनेस को टीम की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए सलीमा ने कहा, हर खिलाड़ी फिटनेस पर काफी मेहनत कर रहा है। किसी भी मजबूत टीम को हराने के लिए फिटनेस बेहद जरूरी होती है। जूनियर खिलाड़ी भी अपनी फिटनेस सुधारने पर ध्यान दे रहे हैं। हमने विश्व कप क्वालीफायर में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी और सुधार की गुंजाइश है।

उन्होंने अर्जेंटीना दौरे को टीम के लिए महत्वपूर्ण अनुभव बताते हुए कहा कि वहां शीर्ष स्तर की टीमों के खिलाफ खेलने से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और टीम संयोजन को बेहतर समझने का मौका मिला।

सलीमा ने कहा, अर्जेंटीना में पूरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहां का अनुभव आस्ट्रेलिया दौरे, नेशंस कप, विश्व कप और एशियाई खेलों की तैयारी में काफी मदद करेगा। हमारा फोकस फिलहाल आस्ट्रेलिया दौरे पर है और हम वहां भी वही लय बरकरार रखना चाहते हैं।

उन्होंने आगे कहा, हम अनुशासित होकर अपनी रणनीति के अनुसार खेलना चाहते हैं। हर खिलाड़ी को अपनी ताकत और कमजोरियों पर काम करना होगा ताकि टीम के रूप में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। दबाव जरूर रहेगा, लेकिन हम उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

भारतीय महिला हाकी टीम 21 मई से 3 जून तक आस्ट्रेलिया दौरे पर रहेगी। इस दौरान टीम पर्थ हाकी स्टेडियम में 26 मई से 30 मई के बीच आस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मुकाबले खेलेगी। यह दौरा न्यूजीलैंड के आकलैंड में आयोजित होने वाले एफआईएच महिला नेशंस कप की तैयारी का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

अब रोबोट होंगे 'बायो-बोट'

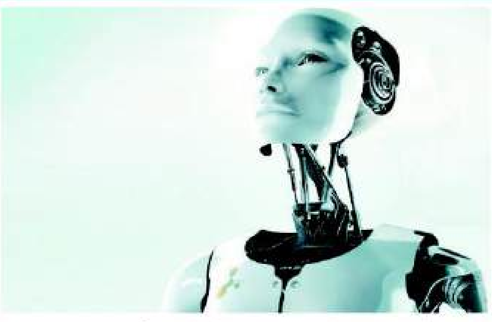

अब वह समय दूर नहीं जब रोबोट्स मानव त्वचा में आना शुरू हो जाएंगे। बायोलॉजिकल रोबोट्स की इस नई पीढ़ी के लिए इंजीनियरों ने कुछ खास सोचा है। वह अब इन्हें मांसपेशियां देने के लिए तैयार हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा तो लगता है, लेकिन 'यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस' के शोधकर्ताओं ने ऐसे रोबोट्स वर्ग का प्रदर्शन किया है जो 'बायो-बोट्स' मांसपेशी कोशिकाओं द्वारा संचालित और बिजली के झटकों के द्वारा नियंत्रित किए जा सकेंगे। इन रोबोट्स को 'बायो-बोट्स' के नाम से जाना जाता है। शोधकर्ताओं का समूह जीव विज्ञान के साथ इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को एकीकृत करके एक ऐसी जैविक मशीन बनाने में लगे हुए हैं, जो पर्यावरण और चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इन बोट्स की खासियत है यह कि वे 'स्केलेटल' मांसपेशी कोशिकाओं के बने हैं। इन मांसपेशियों की कोशिकाओं को 'इलेक्ट्रिक पल्स' द्वारा शुरू किया जा सकता है। इन 'बोट्स' की गति को 'इलेक्ट्रिक पल्स' की फ्रीक्वेंसी को समायोजित करके नियंत्रित किया जा सकता है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर मांसपेशियां ज्यादा जल्दी सिकुड़ती हैं जिससे 'बायो-बॉट' की रफ्तार भी तेज हो जाती है। इससे पहले, शोधकर्ताओं ने चूहों के दिल की कोशिकाओं का उपयोग करके 'बायो-बोट्स' निर्माण करने की कोशिश की थी। लेकिन चूहों के दिल की कोशिकाओं के लगातार सिकुड़ने के कारण शोधकर्ताओं को उसकी गति पर नियंत्रण प्राप्त करने में असफलता प्राप्त हुई। 'स्केलेटल' मांसपेशी कोशिकाओं से शोधकर्ताओं को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। फिलहाल इन रोबोट्स का आकार छोटा होगा और इनका काम शरीर में मौजूद जहरीले पदार्थों के असर को बिल्कुल खत्म करने का होगा। ऐसे 'बोट्स' के निर्माण से यह बात तो स्पष्ट है कि दुनिया भर में वैज्ञानिक ऐसे रोबोट्स बनाने में लगे हुए हैं जो हमारी तरह दिख सकें, हमारे जैसे चल सकें, हमारी तरह बात कर सकें और जो हमारे ही जैसे कार्य कर सकें।

अब ड्रोन से खींचे सेल्फी...

अब तक आपने लोगों को सेल्फी स्टिक से सेल्फी खींचते हुए देखा होगा लेकिन अब सेल्फी स्टिक जल्द ही बीते जमाने की बात हो जाएगी। अब सेल्फी खींचने के लिए ड्रोन का प्रयोग होने लगेगा। आस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने सेल्फी ड्रोन बनाया है। यह सेल्फी ड्रोन बेहतरीन तस्वीरें खींच सकता है और इससे फोटो लेने के लिए आपको अपने हाथ को भी आगे खींचना नही पड़ेगा। इस सेल्फी ड्रोन को ऑस्ट्रेलिया की कंपनी आईओटी ग्रुप ने बनाया है। इसका नाम रोम ड्रोन रखा गया है और यह बाजार में आने से पहले बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जून से बेचा जाएगा। कंपनी की सोच एक स्टेरायड से लैस सेल्फी स्टिक बनाने की थी। सेल्फी स्टिक की समस्या यह है कि जितनी लंबी उसकी डंडी होगी, उतनी ही अच्छी तस्वीरें आएंगी। तो विचार यह है कि ऐसी चीज बनाई जाए जो आपके आसपास उड़ कर आपकी तस्वीर खींचे। इसलिए यह ड्रोन बनाया गया है, जो इतना छोटा है कि बैग या जेब में रखा जा सकता है। इसका आकार 600 मिली पानी के बोतल जितना है। सभी को मालूम है कि ड्रोन उड़ते हुए तस्वीरें खींचते हैं। लेकिन यह उनसे अलग इसलिए है कि यह पोर्टेबल है और इसे दूसरी श्रेणी में रखा जा सकता है।

हैरान करने वाली डिवाइसेस...

गैजेट की दुनिया में आपको कई ऐसी डिवाइसेस मिलेंगी जिनका प्रयोग देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मूज ब्रेन सेंसर भी ऐसा ही अनोखा गैजेट है जो मस्तिष्क के संकेतों को दर्ज करने और ध्यान के समय आपको शांति मिलती है या नहीं, इसका पता लगाता है। मूज ब्रेन सेंसर में अनेक सेंर्स से होते हैं जोकि हैड बैंड से जुड़े होते हैं। यह पुरानी चिंता एवं अवसाद से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इसी तरह कार्बन टाइटेनियम एस-1 प्लस ऑटोमैटिक बार टेंडिग मशीन है जिसे आप अपने स्मार्टफोन पर ऐप की मदद से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप आलस महसूस कर रहे हैं तो आप इस मशीन को केवल एक बटन दबाकर आदेश दे सकते हैं कि वह कॉकटेल तैयार कर दे लेकिन इससे पहले आपको तय करना होगा कि उस जगह पर सारी सामग्री सही हो।

पर्स का वास्तु...

घर का वास्तु, आफिस का वास्तु, आपकी कार का वास्तु, हर चीज में जब आप वास्तु का ध्यान रखते आए हैं तो पर्स में वास्तु का ध्यान क्यों नहीं रखा जा सकता? जिस तरह हमारे आसपास का वातावरण हमें प्रभावित करता है। उसी प्रकार हमारा बैग या पर्स भी हमें प्रभावित करता है। सभी चाहते हैं कि उनका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे और फिजूल खर्च न हो। आय बढ़ाने और फिजूल खर्चों में कमी करने के लिए पर्स का वास्तु भी ठीक करने की आवश्यकता है। कुछ लोग पर्स में ही चाबियां भी रखते हैं,

चाबियां रखना अशुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तु न रखें। फिजूल वस्तुओं को तुरंत निकाल दें। पर्स में सिक्के और नोट दोनों ही अलग-अलग स्थानों पर रखने चाहिएं। पर्स में मृत व्यक्तियों के चित्र रखना भी शुभ नहीं माना जाता। पर्स में संत-महात्मा के चित्र रखे जा सकते हैं। यदि कोई संत या महात्मा देह त्याग चुके हैं तब भी उनके चित्र या फोटो पर्स में रखे जा सकते हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार देह त्यागने के बाद भी संत-महात्माओं को मृत नहीं माना जाता। पर्स में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें। इनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। इन्हें भी रुपए-पैसों से अलग ही रखना शुभ है। पर्स में नोट या सिक्कों के साथ खाने की चीजें नहीं रखनी चाहिएं। पर्स में किसी भी प्रकार के बिल या भुगतान से संबंधित कागज नहीं रखने चाहिए। अपने पर्स में एक लाल रंग का लिफाफा रखें। इसमें आप अपनी कोई भी मनोकामना एक कागज में लिख कर रखें। वह शीघ्र पूरी होगी। रात्रि में सोते समय पर्स कभी भी सिराहने न रख कर उसे हमेशा अलमारी में रखें। अपने पर्स में किसी पूर्णिमा को लाल रेशमी कपड़े में चुटकी भर या 21 दाने अखंडित चावल बांध कर छुपा कर रखने से बेवजह खर्च नहीं होता है।

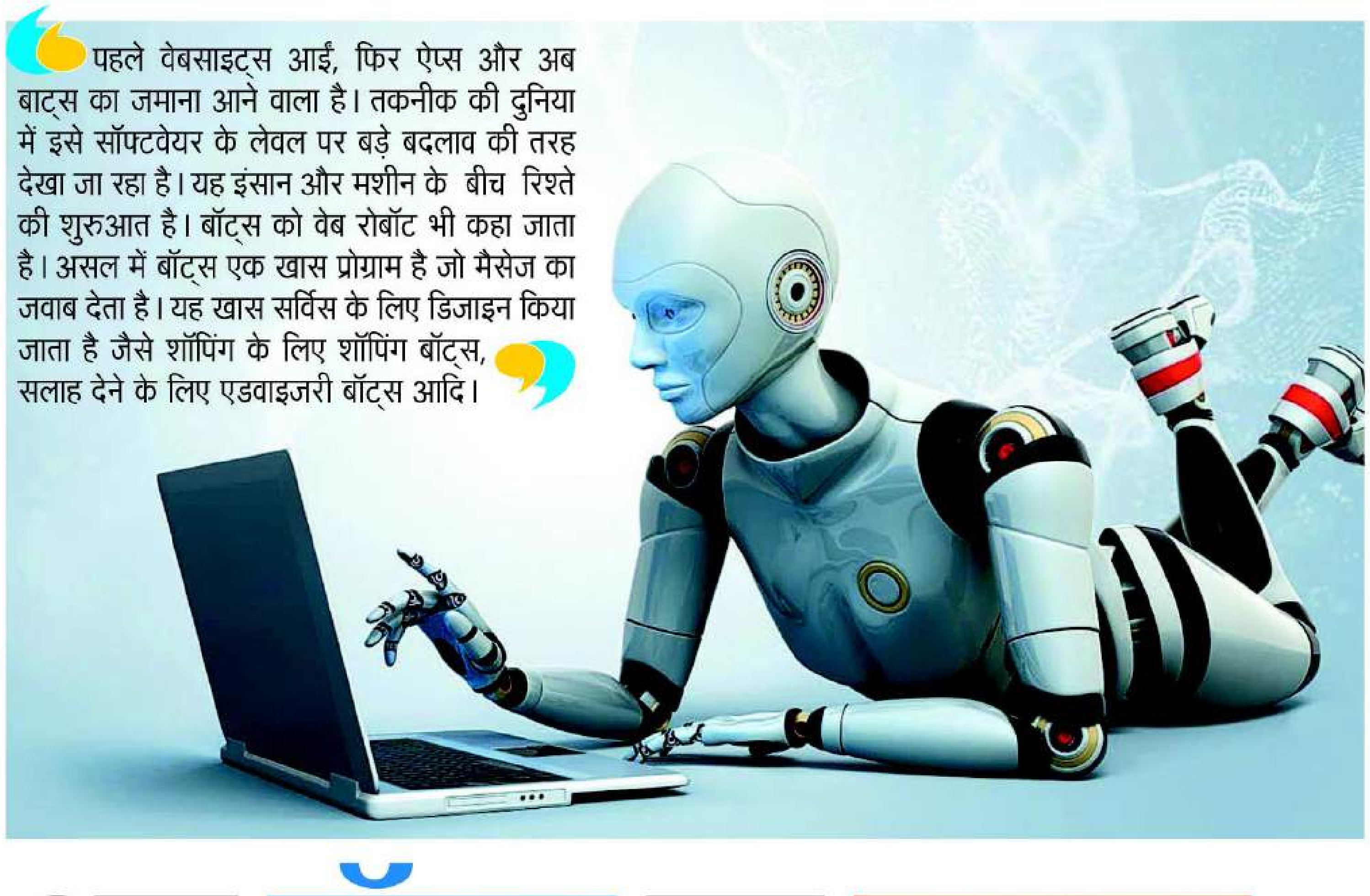

पहले वेबसाइट्स आई, फिर ऐप्स और अब बाट्स का जमाना आने वाला है। तकनीक की दुनिया में इसे सॉफ्टवेयर के लेवल पर बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है। यह इंसान और मशीन के बीच रिश्ते की शुरुआत है। बॉट्स को वेब रोबॉट भी कहा जाता है। असल में बॉट्स एक खास प्रोग्राम है जो मैसेज का जवाब देता है। यह खास सर्विस के लिए डिजाइन किया जाता है जैसे शॉपिंग के लिए शॉपिंग बॉट्स, सलाह देने के लिए एडवाइजरी बॉट्स आदि।

अब बॉट्स का जमाना...

21वीं सदी में चूंकि हर दिन एक नई तकनीक आपके सामने आ रही है इसलिए आपके लिए यह जरूरी हो गया है कि पुरानी तकनीक को छोड़ कर आगे बढ़ें और अपडेटेड रहें। पहले लोगों के लिए वेबसाइट आई, फिर आए मोबाइल ऐप्स लेकिन अब इसके भी आगे की चीज आ गई है जो जल्द ऐप्स की जगह ले सकती है और वो है बॉट्स। जी हां, इसको मनुष्य और मशीन के बीच की एक नई अहम कड़ी माना जा रहा है। साथ ही, यह इंसानों से बात करने और उनकी इच्छा को भापने का एक नया माध्यम बन गया है। अभी आपको कंप्यूटर पर काम करने के लिए कंप्यूटर जैसा बनना पड़ता है लेकिन भविष्य में बॉट्स इंसानों की तरह काम करने को तैयार हैं।

क्या हैं बॉट्स ?

बॉट्स तकनीकी दुनिया की एक नई खोज है जो आपको कंप्यूटर पर अपने तरीके से काम करने की सहूलियत देती है। इन बॉट्स को इंटरनेट के रोबॉट के नाम से जाना जाता है। असल में बॉट्स एक ऐसा नया और खास प्रोग्राम है जिसे मेसेज का जवाब देने के लिए बनाया गया है। ये हर सर्विसेज के लिए अलग बने होते हैं जैसे कि हेल्थ सलाह देने के लिए हेल्थ बॉट्स, वेदर अपडेट के लिए वेदर बॉट्स, शॉपिंग के लिए शॉपिंग बॉट्स, सलाह देने के लिए एडवाइजरी बॉट्स आदि। ये बॉट्स सॉफ्टवेयर और एप्स जैसे ही बनते हैं। इन बॉट्स को अपने या कस्टमर के हिसाब से बनाया जा सकता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर को अच्छी तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिए हैं जिससे कोई भी बिना मशक्कत के कोडिंग करके इसे बना सकता है। फिलहाल ऐसी कई कंपनियां हैं जो यह प्लेटफॉर्म लोगों को उपलब्ध करा रही हैं जैसे फेसबुक, स्लैक, किक, गपशप आदि। इस सॉफ्टवेयर का कोडिंग का एक सेट लेआउट होता है जिसे प्रोग्रामर जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड कर सकता है।

क्या जरूरत है बॉट्स की?

फिलहाल लोग मूल रूप से वेबसाइट और ऐप्स के जरिए ही अपनी जरूरतों तक पहुंचते हैं। जहां लोग मैसेजिंग ऐप्स से हर वक्त एक्टिव रहते हैं वहीं कोई चीज ढूंढने या कोई जानकारी लेने के लिए लोगों को दूसरी साइट या ऐप प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है। ऐसे में हर कंपनी का मकसद अपने कस्टमर को अच्छी सहूलियत पहुंचाना बन जाता है। कस्टमर की इसी परेशानी का हल बने हैं ये बॉट्स। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहीं जाना है और आपको कैब बुक करानी है तो आपको पहले उसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और तब बुकिंग करानी पड़ेगी। लेकिन बॉट्स के जरिए आपकी परेशानी का हल निकल जाता है। इससे न तो आपको बार-बार वेबसाइट पर जाना पड़ता है और न ही ऐप को बार-बार क्लिक करना पड़ता है। आप अपनी मैसेजिंग ऐप से ही कैब या कोई भी अन्य काम कर सकते हैं। इस सुविधा के लिए आपको कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा बल्कि बॉट्स बनाने या चलाने का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ही करेगी।

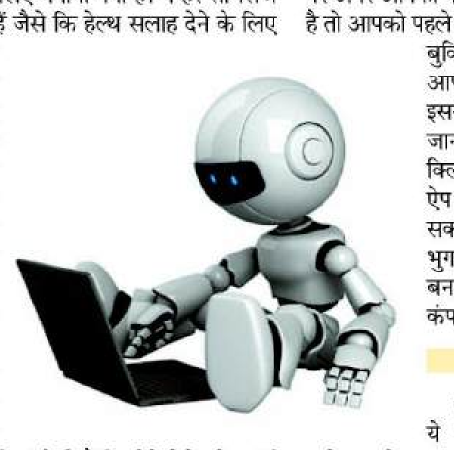

कहां हो रहा इतेमाल

बॉट्स भले ही हमारे के लिए नए हों परंतु ये बॉट्स कॉरपोरेट लेवल पर कबके इस्तेमाल होना शुरू हो चुके हैं। कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से लेकर कई और डिपार्टमेंट तक इन बॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस बॉट्स का इस्तेमाल कंपनियां एंप्लॉयीज को फीडबैक लेने और देने के लिए कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां इसका भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। दुनियाभर में कई ऐसी कंपनियां हैं जो इन बॉट्स को इस्तेमाल करने का मन बना रही हैं।

कैसे बनाए जाते हैं बॉट्स

यह कुछ उसी तरह बनते है जैसे वेबसाइट्स और ऐप बनते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इसको अपनी या कस्टमर की जरुरत के हिसाब से डिजाइन कर सकता है, लेकिन इन्हें बनाने के लिए काफी तकनीकी ज्ञान की जरुरत होती है। कुछ कंपनियो ने इनके प्लेटफॉर्म बना कर इसे काफी हद तक आसान बना दिया है।

आ गए हैं कई बॉट्स

फिलहाल कई मैसेजिंग ऐप्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने चैटबॉट्स लॉन्च कर दिए हैं उनमें सब कुछ नाम हैं फेसबुक, स्लैक, टेलेग्राम, हिपचैट और किक। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी मेटलाइफ, फिलपकार्ट, ओला और मेरू कैब जैसी कंपनियों ने बॉट्स का इस्तेमाल इन-हाउस ऑपरेशंस के लिए शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिनों पहले फेसबुक मैसेंजर पर हेल्थ कंसल्टेंसी लाइब्रेट और ऑटो एग्रीगेटर जुगनू ने अपने बॉट्स लॉन्च किए है। लाइब्रेट से यूजर्स हेल्थ से संबंधित और जुगनू से अपना ऑटो बुक आसानी से करा सकता है। यदि चैट करते वक्त आपको भूख लगे तो आप पिज्जा के बॉट्स पर जाकर वैरायटी या रेंज के सवाल पूछ सकते हैं और इसके साथ ही आप आर्डर भी बुक कर सकते हैं और आनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं।

ऐप्स को पीछे छोड़ेंगे

अगर बात करें बॉट्स के रिसपॉन्स की तो अभी ये उतने दमदार नहीं हैं। धीमे चलने वाले ये बॉट्स सवाल का जवाब बहुत जेनरिक या काफी सामान्य देते हैं। कई बार ये सवाल समझने में नाकाम रहते हैं या तो सवाल का सही जवाब नहीं देते हैं। कभी-कभी फनी बॉट्स गालियों का इस्तेमाल चैट में करने लगते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद ये धीरे-धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। हां, इतना जरूर है कि आने वाले समय में ये बॉट्स ऐप्प को पीछे छोड़ सकते हैं और हमारी जिंदगी में एक अहम हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसकी क्षमता बढ़ाने और इसे बेहतर बनाने में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है।

कैसे शुरू करना है

इस सर्विस को एक्टिव करना काफी आसान है। फेसबुक मैसेंजर पर लाइब्रेट नाम के चैट बॉट को एक्टिव करके हेल्थ सवालों का जवाब मिल सकता है इसे एक्टिव करने के लिए ऐड का ऑप्शन है।

चेहरे या आवाज को बनाएं पासवर्ड...

सभी लोग अपने स्मार्टफोन और टैबलेट की सिक्योरिटी को लेकर परेशान हैं। सिक्योरिटी के लिए तरह-तरह की कोशिश की जा रही है। कभी पैटर्न लॉक लगाया जाता है, कभी पिन इस्तेमाल किया जाता है तो कभी पासवर्ड लगाकर देखा जाता है। सभी के अपने फायदे हैं। यही सिक्योरिटी आपके लिए तब सिरदर्द बन जाती है, जब हर बार आपको अपने पिन, पासवर्ड या पैटर्न लॉक का इस्तेमाल करना होता है ताकि अपने डिवाइस को इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड्राइड डिवाइस पर अपने चेहरे को पहचान कर भी ऐसा करना अब संभव है। अगर अपने डिवाइस पर आप ये इनेबल कर देते हैं तो ये पिन, पासवर्ड या पैटर्न लॉक की जरूरत ही खत्म हो जाएगी और सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत सुरक्षित भी होगा क्योंकि आपके जैसा दिखने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा शायद सिर्फ फिल्मों में होता है।

शुरू करना आसान

फेस रिकग्निशन एंड्राइड डिवाइस और क्रोम बुक के स्मार्ट लॉक नाम के फीचर का हिस्सा होता है। इसको शुरू करना बहुत ही आसान है। बस सिक्योरिटी में जाइए और उसके बाद आपको स्मार्ट लॉक दिखाई देगा। इसको देखने के लिए अपने डिवाइस में आपको स्क्रीन लॉक को एक्टिवेट करना होगा। स्मार्ट लॉक का इस्तेमाल करके आप अपने डिवाइस को अलग अलग तरीके से अनलॉक करने के लिए सेटिंग कर सकते हैं। इसे आप किसी भी अपने दूसरे डिवाइस के साथ जोड़ा बना सकते हैं, अपने चेहरे को भी पासवर्ड बना सकते हैं या फिर अपनी आवाज को।

ऐसे लें तस्वीर

एंड्राइड डिवाइस पर जब आप अपने चेहरे को पासवर्ड बना रहे हैं तो अपनी तस्वीर लेते समय रोशनी बढ़िया होनी चाहिए। स्क्रीन पर आपको एक गोल दिखाई देगा जिसके अंदर आपकी तस्वीर होनी चाहिए। एक बार पासवर्ड के लिए अपने चेहरे को आपने सेट कर लिया, उसके बाद बस स्क्रीन को कुछ सेकेंड के लिए देखिए उसके बाद आप स्क्रीन को स्वाइप कर अनलॉक कर सकते हैं।

ढेर सारे ऐप

कुछ एंड्राइड डिवाइस में आपको यह फीचर नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर यह फीचर आपको चाहिए तो ये काम करने वाले ढेर सारे ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। वैसे ही वॉइस लॉक करने वाले ऐप भी कई मिल जाएंगे।

नौकरी पाने के लिए न दें झूठी जानकारी

जल्द नौकरी हासिल करने या अत्यधिक महत्वाकांक्षा के चलते उम्मीदवार नौकरी मांगने के दौरान कई बार योग्यता संबंधी ऐसी जानकारी दे देते हैं, जो उनके पास होती ही नहीं। हकीकत सामने आने पर वे जॉब से तो वंचित हो ही जाते हैं, उनके आगे की राह भी कठिन हो जाती है।

एक सर्वे के अनुसार वर्तमान समय में ज्यादातर संस्थान अपने कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्रों में गड़बड़ियों की समस्या से जूझ रहे हैं। एक कंपनी छोड़ दूसरी ज्वाइन करने पर दोनों में दी गई जानकारी में भी काफी अंतर देखने को मिल रहा है। यह सही है कि कंपनियां जॉब देते समय उम्मीदवार के पिछले तीन-चार साल का अनुभव, शैक्षिक योग्यता और अंतिम 4-5 साल का पता खंगालती हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियां सीनियर पद पर किसी को ज्वाइन कराते वक्त लचीला रुख अपनाती हैं।

वे उम्मीदवार के प्रोफाइल व पैकेज को ही आधार बनाती हैं। सर्वे बताते हैं कि भारत ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी ऐसे उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है, जो बायोडाटा में अपनी उपलब्धियों, अनुभव और शैक्षिक योग्यताओं के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर लिखते हैं। बाद में वेरिफिकेशन के दौरान उनकी गलतियां उजागर होती हैं। इन नेगेटिव वेरिफिकेशन रिपोर्ट से न सिर्फ उनकी नौकरी जाती है, बल्कि इंडस्ट्री में उनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है।

नहीं मिल पा रहे सही लोग

ग्लोबलाइजेशन और जॉब मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते हर कंपनी चाहती है कि वह कुशल व प्रतिभाशाली कर्मचारियों को नियुक्त करे। देश में जितनी ज्यादा नौकरियां हैं, उससे कई गुना ज्यादा नौकरी ढूंढने वाले लोग। हर साल देश में लगभग 23 लाख ग्रेजुएट पैदा होते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर को उनकी पढ़ाई और स्किल्स के मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों में 61 प्रतिशत पद खाली हैं। सबसे ज्यादा अवसर सेल्स, आईटी, अकाउंटिंग, फाइनेंस व ऑफिस सपोर्ट जैसे सेक्टरों में मौजूद हैं। इनमें सही टैलेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आवेदन के समय उम्मीदवार अपनी उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ा कर लिख रहे हैं या झूठी सूचनाएं दे रहे हैं।

दें सही जानकारी

एक अच्छी नौकरी पाने की तलाश में जुटे उम्मीदवार कई बार अपने रेज्यूम में भ्रामक सूचनाएं दे जाते हैं। इसके चलते उन्हें शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए यदि आप किसी नई नौकरी के लिए रेज्यूम देने जा रहे हैं तो

ऐसे होती है हेराफेरी

क्वालिफिकेशन : उम्मीदवार आवेदन के दौरान कई बार ऐसी शैक्षिक योग्यता का जिक्र कर बैठते हैं, जो उनके पास होती ही नही या गलत तरीके से हासिल की गई होती है। ज्यादातर संस्थानों मे आवेदन के दौरान ऐसा देखने को मिलता है। बैकग्राउंड चेकिंग फर्म्स के जरिए ऐसे फ्रॉड को पकड़ा जाता है।

फर्जी डिग्री: देश में कई ऐसे संस्थान चल रहे है, जिनकी मान्यता नही है या उनके कोर्स को संबंधित अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त नही है। वहां की डिग्री फर्जी डिग्री की श्रेणी में आती है। कई बार अज्ञानता में तो कई बार जान-बूझ कर उम्मीदवार इन डिग्रियों का इस्तेमाल करते हैं।

सैलरी पैकेज: एक कपनी से दूसरी कपनी ज्वाइन करने पर सबसे अहम फैक्टर सैलरी पैकेज होता है। मोटा पैकेज पाने की चाहत में उम्मीदवार या तो अपनी स्लिप से छेड़छाड़ करते है या फर्जी सेलरी स्लिप बनवाते है। एचआर डिपार्टमेंट की छानबीन में इस तरह के मामले पकड़ में आ जाते हैं।

एक्सपीरिएंस: उम्मीदवार एक्सपीरिएंस सर्टिफिकेट के रूप में अकसर किसी ऐसे संस्थान से 2-3 साल का अनुभव दर्शाते हैं, जो वर्तमान में बंद हो चुका होता है या उसकी पुष्टि नही हो पाती। कई बार वे अनुभव के साल बढा-चढा कर दिखाते हैं। वे मान कर चलते हैं कि उनका खेल पकड़ मे नही आएगा, पर वेरिफिकेशन में इस खेल से पर्दा उठ जाता है।

मैरिटल स्टेटस: सैन्य अथवा कई ऐसे सेवा क्षेत्र है, जिनमें अविवाहित उम्मीदवारों से आवेदन मांगा जाता है। ऐसे नौकरी के लिए विवाहित उम्मीदवार अकसर अपनी पहचान छुपा लेते हैं। इस आधार पर वे कई साल नौकरी भी कर लेते है। बैकग्राउड अथवा एड्रेस वेरिफिकेशन में इसका पता चलता है।

क्रिमिनल रिकॉर्ड: उम्मीदवारो पर नौकरी के लिए आवेदन देने से पूर्व यदि कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है तो वे आवेदन में इसका उल्लेख नहीं करते। इस तरह की प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों को कोई भी अपने यहां नहीं रखना चाहता। हेल्थकेयर व फाइनेंशियल कपनियां ऐसी पृष्ठभूमि की जांच करवाती हैं।

अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों और उपलब्धियों के बारे में बताने से पहले विशेष सावधानी बरतें। जॉब की जरूरत के हिसाब से अपनी स्किल्स मैच कराएं। एक-एक बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख करें, दूसरों का सीवी कॉपी करने से पहले बचें।

कंपनी का नुकसान

गलत सूचना देकर नौकरी हासिल करने वाले कर्मचारियों की मंशा कंपनी को नुकसान पहुंचाने की बेशक न हो, लेकिन वह उसकी कार्यनीति और परंपरा को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। गलत सूचना देकर नौकरी हासिल करने पर कंपनी को अपने प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले अयोग्य प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग में पैसा लगाना पड़ता है। इससे उनको भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है।

सुरक्षा की दृष्टि से घातक

अपने बारे में गलत सूचना देने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार पद पर बैठाना कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से घातक हो सकता है। चूंकि कंपनियों को गोपनीय सूचनाएं या डेटा लीक होने का खतरा रहता है, इसलिए ज्यादातर कंपनियां किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से पहले उसकी पूरी छानबीन कराती हैं। कोई कंपनी कभी नहीं चाहती कि ऐसे लोगों को अपने यहां जॉब दे, जिनकी बुनियाद ही झूठ के सहारे रखी गई हो।

ऑनलाइन मॉनीटरिंग

आजकल कई ऐसे एप प्रचलन में हैं, जिनके जरिए उम्मीदवार अपनी योग्यता, अनुभव व अन्य विवरण ऑनलाइन भेज सकते हैं।

इसके लिए आवेदनकर्ता और नियोक्ता दोनों का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इस आईडी नंबर के जरिए वे उम्मीदवार का पूरा वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यह ऐप जल्द ही सोशल मीडिया 'डिजिटल टैलेंट पूल' के जरिए लोगों को नौकरी पर रखे जाने की प्रक्रिया में अहम भूमिका अदा करेंगे। कंपनियां भी एप्लिकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं, जो सीवी का विश्लेषण करता है।

इसलिए आ रही दिक्कत

एक सर्वे के मुताबिक भारत में जितनी नौकरियां पैदा हो रही हैं, उनमें से करीब 90 प्रतिशत के लिए खास स्किल्स की जरूरत पड़ती है।

इसकी ट्रेनिंग स्कूल-कॉलेज अथवा इंस्टीट्यूट में नहीं मिल पा रही, लिहाजा बड़ी आबादी बेरोजगारी का दंश झेल रही है। जल्दी नौकरी पाने की चाहत में उम्मीदवार कई बार झूठी सूचनाएं देकर नौकरी हासिल करने की कोशिश करते हैं या अपने नकारात्मक पहलुओं को छिपाने का प्रयास करते हैं।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**